

चिंतन

तनाव के बाद राहत की नई शुरुआत

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने न केवल वैश्विक शांति बल्कि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, आपूर्ति बाधित होने की आशंका और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी थीं, लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और इसके साथ राहत के संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। एक जुलाई से लागू हुए कई बदलाव यह भरोसा दिलाते हैं कि संकट के बाद बेहतर दौर की शुरुआत संभव है। इसे तनाव के बाद राहत की नई शुरुआत माना जा रहा है। सबसे बड़ी राहत ऊर्जा क्षेत्र से मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटकर करीब 73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं। इसका असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नायाग एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। यह केवल कीमतों में कमी नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि वैश्विक परिस्थितियां सामान्य होने का लाभ अब आम उपभोक्ता तक पहुंचने लगा है। अब उम्मीद की जा सकती है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह नियंत्रित रहें तो अन्य तेल कंपनियों भी जल्द राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाएंगी। महंगाई पर नियंत्रण की दिशा में एक और सकारात्मक खबर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में औसतन 180 रुपये की कमी है। इससे होटल, रेस्तरां और छोटे कारोबारियों की लागत घटेगी। यदि यह लाभ ग्राहकों तक पहुंचता है तो बाहर खाना, छोटी-बड़ी कैंटीन और कई सेवाएं अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती हैं। डीजल भरवाने की दैनिक सीमा हटने से परिवहन और उद्योग जगत को भी राहत मिलेगी, जिससे माल ढुलाई सुचारू होगी और बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता बेहतर बनेगी। इसी बीच प्रकृति ने भी राहत का संदेश दिया है। मानसून ने देश के अधिकांश हिस्सों में दस्तक दे दी है। अच्छी बारिश किसानों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आती है। खेतों में हरियाली बढ़ती है, फसल की उम्मीद मजबूत होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है। कृषि उत्पादन अच्छा रहने पर खाद्य महंगाई पर भी नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। ऐसे में बारिश और ईंधन क्षेत्र से मिली राहत मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर सकती है। हालांकि पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी और बिना टिकट यात्रा पर जमाना बढ़ना कुछ लोगों की जेब पर असर जरूर डालेगा, लेकिन व्यापक तस्वीर देखें तो एक जुलाई कई ऐसे बदलाव लेकर आया है जो अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन में सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। संकट के दौर के बाद ऐसे छोटे-छोटे कदम ही लोगों में विश्वास जगाते हैं कि हालात सुधर रहे हैं। भारत ने हमेशा कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और संतुलन से किया है। आज भी दुनिया जब भू-राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब राहत के ये संकेत केवल आर्थिक आंकड़ों नहीं, बल्कि उम्मीद के प्रतीक हैं। यदि वैश्विक शांति बनी रहती है, कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और मानसून अनुकूल रहता है, तो आने वाले वर्षों में महंगाई पर और लगाम लग सकती है तथा आर्थिक गतिविधियां नई रफ्तार पकड़ सकती हैं। कुल मिलाकर कह जा सकता है कि यदि ईंधन की कीमतों में और कमी आती है, महंगाई नियंत्रित रहती है और कृषि उत्पादन बेहतर होता है, तो यह केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती की नई शुरुआत साबित हो सकती है। आखिरकार किसी भी नीति की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि उसका लाभ आम आदमी को थाली, जेब और जीवन में कितना दिखाई देता है।

मंथन

ममता कुशवाहा



आराम की दौड़ में आखिर सुरक्षा से समझौता क्यों

नो एडा के एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में हाल ही में एयर कंडीशनर (एसी) में ह्यू विसफ्रेट से लगी आग ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आधुनिक सुविधाएं यदि सावधानी के साथ न अपनाई जाएं तो वही जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को कई घंटे लग गए। इससे पहले भी देश के विभिन्न शहरों में एसी फटने या उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन हादसों ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल तकनीक पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। भीषण गर्मी के इस दौर में एयर कंडीशनर अब केवल विलासिता का साधन नहीं रह गया है। पहले जहां एसी केवल बड़े घरों, कार्यालयों या होटलों तक सीमित था, वहीं आज मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में भी यह आम जरूरत बन चुका है। लगातार बढ़ते तापमान और बदलती जीवनशैली ने एसी को रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना दिया है। लेकिन सुविधा का यह साधन तभी तक उपयोगी है, जब तक उसका उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाए। जैसे-जैसे एसी का उपयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे उससे जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है।

यह स्थिति केवल व्यक्तिगत लापरवाही का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी खामियां, घटिया गुणवत्ता वाले उपकरण, अपर्याप्त रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी समाान रूप से जिम्मेदार हैं। यद्यपि समय-समय पर प्रशिक्षित तकनीशियन से एसी की जांच कराई जाए, गैस का स्तर देखा जाए और बिजली की वायरिंग की स्थिति पर ध्यान दिया जाए, तो अधिकांश हादसों को रोका जा सकता है। बढ़ती दुर्घटनाओं के पीछे एक और चिंता का विषय बाजार में उपलब्ध निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कई कंपनियां कम कीमत पर उपकरण बेचने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर लेती हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता भी कम कीमत के लालच में बिना प्रमाणित उत्पाद खरीद लेते हैं। ऐसे उपकरणों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता और उनमें प्रयुक्त पुर्जें भी टिकाऊ नहीं होतीं। परिणामस्वरूप थोड़ी-सी तकनीकी खराबी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। इसलिए उपभोक्ताओं को हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद कंपनियों के उत्पाद ही खरीदने चाहिए। यह समस्या केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी विकास और भवन निर्माण व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। आज महानगरों में ऊंची-ऊंची इमारतें तेजी से बन रही हैं, लेकिन उनमें अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन हमेशा संतोषजनक नहीं होता। परिणामस्वरूप छोटी-सी आग भी भयावरूप रूप धारण कर लेती है। दमकल विभाग की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देश के अनेक शहरों में संसाधनों और आधुनिक उपकरणों का अभाव है। ऊंची इमारतों तक पहुंचने वाली हाइड्रोलिक सीढ़ियां और उच्च क्षमता वाले अग्निशमन उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। कई बार संकरी सड़कें, अवैध पार्किंग और अव्यवस्थित यातायात भी दमकल वाहनों के समय पर पहुंचने में बाधा बन जाते हैं। ऐसे में आग पर नियंत्रण पाने में देरी होती है और नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन भी इस समस्या को और गंभीर बना रहा है।

हर वर्ष तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे एसी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। बिजली की मांग बढ़ने से विद्युत व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कई क्षेत्रों में पुरानी वायरिंग और ओवरलोड ट्रांसफार्मर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा देते हैं। इसलिए ऊर्जा अवसंरचना को भी समय के अनुरूप आधुनिक बनाना आवश्यक है, ताकि बढ़ती जरूरतों को सुरक्षित ढंग से पूरा किया जा सके। वास्तव में आधुनिक तकनीक का उद्देश्य जीवन को सरल और आरामदायक बनाना है, न कि उसे संकट में डालना। इसलिए सुविधा और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नोएडा जैसी घटनाएं केवल समाचार नहीं हैं, बल्कि चेतावनी हैं कि यदि हम अभी भी नहीं चिंते तो भविष्य में ऐसे हादसे और बढ़ सकते हैं। सरकार को सुरक्षा मानकों का कठोर पालन सुनिश्चित करना होगा, भवन निर्माताओं को अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने होंगे और नागरिकों को जिम्मेदार उपभोक्ता बनना होगा। जब तकनीक के साथ सतर्कता, गुणवत्ता के साथ-साथ जिम्मेदारी और सुविधा के साथ सुरक्षा भी जुड़ जाएगी, तभी आधुनिक जीवन वास्तव में सुरक्षित, सुखद और विश्वासपूर्ण बन सकेगा।

(लेखक शिक्षक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



कोर्ट का फैसला

प्रमोद भार्गव

अदालत ने कहा कि धर्म बदलने वाला व्यक्ति 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' का दर्जा मांगने का अधिकार नहीं रखता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी अलग-अलग समुदाय और वर्ग होते हैं, परंतु उनकी पहचान जन्म से तय होती है न कि धर्म परिवर्तन से? अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामिक उपदेशक और ईसाई मिशनरियां सदियों से यह प्रचार करती आई हैं कि उनके धर्मों में सामाजिक समानता है, जबकि हिंदू धर्म में जाती व्यवस्था एक बुनियादी विसंगति है। अतएव धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद यह कहना बेमानी है कि इस्लाम में भी ऊंच-नीच या वर्गभेद है। हमारी राय में कुछ मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा और कुछ को अगड़ा मानना कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है। दरअसल इस्लाम एक ऐसा समाज बनाता चाहता है, जिसमें सब का दर्जा एक समान रहे। यह ऐतिहासिक फैसला न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की पीठ ले दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार के तीन मार्च 2024 के आदेश को आधार बनाया था। इसमें आरक्षित श्रेणियों से धर्मांतरित लोगों को तमिलनाडु में अधिसूचित सात पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समूहों में से एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता था। सरकार ने अपने आदेश में यह प्रावधान किया था कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग या डी-नोटिफाइड समुदायों से आने वाले व्यक्ति यदि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग मुस्लिम की श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस सिस्लसिले में सरकार का तर्क था कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक संतुलन बना रहेगा, किंतु अदालत ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। इसी से मिलती-जुलती प्रकृति के एक एक मामले में फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि बिना किसी वास्तविक आस्था के केवल आरक्षण के लाभ हेतु किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सी सेल्वरानी की याचिका पर 26 नवंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के 24 नवंबर के उस फैसले को बरकरार

इस्लाम धर्म अपनाने पर आरक्षण नहीं

रखा, जिसमें ईसाई धर्म अपना चुकी एक महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। महिला ने बाद में आरक्षण के तहत रोजगार का लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया था, लेकिन इस पीठ ने फैसले में साफ किया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है, जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और धर्म आधारित आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। यदि धर्म परिवर्तन का मकसद दूसरे धर्म में वास्तविक आस्था होने की बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी गलत इच्छा रखने वाले लोगों को आरक्षण



का लाभ देने से आरक्षण नीति के सामाजिक व्यवहार को क्षति पहुंचेगी। बावजूद सेल्वरानी हिंदू होने का दावा करती हैं और नौकरों के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मांगती हैं, तब यह दोहरा दावा अस्वीकार्य है। साफ है, वह ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकती हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी तारतम्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध भी अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को

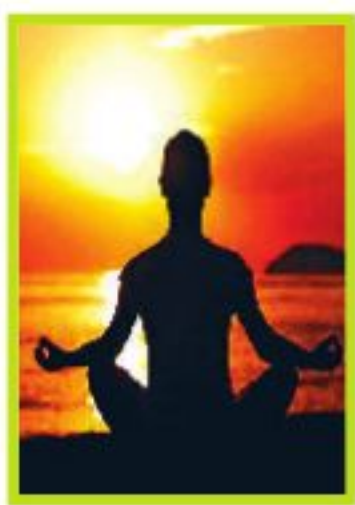
नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है, परंतु उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार राज्यों को है, केंद्र को नहीं। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुरतनी जमाने से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं से ये आज भी वंचित हैं।

संविधान के अनुच्छेद-342 में धर्म परिवर्तन के संबंध में अनुच्छेद-341 जैसे प्रावधान में लोच है। 341 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस कारण यह वर्ग धर्मांतरण से बचा हुआ है। जबकि 342 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के आदि मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी कि अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अधिसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुसंसा पर दिया जाता है। इस आदेश के लागू होने पर उल्लेखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आदेश के लागू होने के उपरांत भी इसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1956 में एक संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान किया गया था कि यदि इस जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकारता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, किंतु यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों के वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं, जो भारतीय धर्म हिन्दू, बौद्ध और सिख अपनाने वाले हैं। गोया, अनुच्छेद-342 में 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण को समस्या पर स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाएगा। अनुसूचित जातियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि ईसाई या इस्लाम धर्मावलंबी बने अनुसूचित जाति के लोग केवल नौकरों के लिए फिर से धर्म परिवर्तन कर हिंदू नहीं बन सकते हैं। यह उपाय आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होने के साथ संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यह उपाय आरक्षण नीति के मौलिक समाजिक लक्ष्यों को कमजोर करता है। अतएव ऐसे उपाय हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य के तहत आरक्षण नीतियों की मूल भावना के विपरीत हैं।

(लेखक बरिष्ठ सलाहकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अर्जी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मन को स्थिर रखना ही है जीवन का सूत्र



संकलित

दर्शन

काम, क्रोध, लोभ और मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असतुष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है, तो उसे यह संसार खरानुमा लगने लगता है। काम अर्थात् इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठे इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसकी यह इच्छापूर्ति उसी तरह से उसके मन में एक और इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देगी, जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्र में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु और वेग से जलने लगती है। इसी भांति से यदि अन्य किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता होती है तो वे दोनों ही पक्ष एक-दूसरे को हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चित्त की सहज शांति खो बैठते हैं। इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता ही है, जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाली संभावित प्रतिक्रिया से हर दम चिंतन में डूबा रहता है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही बनता है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो, जिसकी बराबरी धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं न कर सके और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला न हो सके। रावण से लेकर कंस आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं, जो अपने जीवन में अपनी ऐसी ही मानसिक विकृतियों से कभी भी पार नहीं पा सके।

अंतर्मन



करंट अफेयर

अमेरिकी डाक सेवा दिवाली पर जारी करेगी डाक टिकट

अमेरिकी डाक सेवा (यूएसपीएस) ने दिवाली के त्योहार पर आधारित एक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। यह टिकट इस वर्ष के अंत में जारी किया जाएगा। दिवाली के इस डाक टिकट पर ह्यूस्टन की कलाकार संगीता भूटाडा द्वारा बनाई गई रंगोली की आकृति है जिसकी तस्वीर बिनय दीक्षित ने ली थी। यूएसपीएस ने कहा कि रंगोली पत्र पर की जाने वाली एक खूबसूरत कलाकारी है जिसे पारंपरिक रूप से चावल के रंगीन पाउडर, चोंक और फूलों की पेंसुडियों जैसी सामग्री से बनाया जाता है तथा इसे शुभ माना जाता है। यूएसपीएस के अनुसार, भूटाडा मूल रूप से भारत की रहने वाली हैं और लंबे समय से ह्यूस्टन क्षेत्र में रह रही हैं। वह करीब 30 वर्षों से रंगोली की प्राचीन लोककला से जुड़ी हुई हैं। इस डाक टिकट को जेनिफर अनील्ड ने डिजाइन किया है और विलियम जे. गिंकर इसके कला निदेशक हैं। यूएसपीएस ने बताया कि दिवाली पर आधारित यह डाक टिकट अक्टूबर में जारी किया जाएगा। यूएसपीएस ने कहा, 'हिंदू पंचांग के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में शामिल दिवाली हर वर्ष शरद ऋतु में मनाई जाती है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली आमतौर पर पांच दिन तक मनाई जाती है। वर्ष 2026 में त्योहार का मुख्य दिन आठ नवंबर को होगा।'



सत्र साल पहले पृथ्वी का सिर्फ एक ही प्राकृतिक उपग्रह था- चंद्रमा। आज पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों की संख्या 15,000 से अधिक हो चुकी है, जिनमें से लगभग 10,000 एलन मस्क की कंपनी 'स्पेसएक्स' के हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क की योजना 10 लाख और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर और चौड़ाई करीब 20 मीटर होगी तथा ये मिलकर अंतरिक्ष में डेटा केंद्रों के रूप में काम करने वाला एक विशाल उपग्रह समूह बनाएंगे। अंतरिक्ष कवर से आशय पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उन सभी वस्तुओं से है, जिनका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। इनमें इस्तेमाल हो चुके रॉकेट के हिस्से, निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त उपग्रह तथा अति सूक्ष्म कण भी शामिल हैं। वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में 10 सैटीमाइटर से बड़े कचरे के करीब 36,000 टुकड़े हैं, जबकि इससे छोटे कणों की संख्या करोड़ों में है। अनुमान है कि इस पूरे मलबे का कुल वजन 13,486 टन है। इस मलबे में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका, रूस और चीन का है। अंतरिक्ष मलबा इस्लॉय बंदर खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति सैकंड की औसत गति से पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहा होता है। इतनी तेज गति से होने वाली एक टक्कर किसी उपग्रह को पूरी तरह तोड़ सकती है तथा उससे और भी अधिक अंतरिक्ष मलबा पैदा हो सकता है।

आज की पाती

साइबर सुरक्षा के लिए जनचेतना जरूरी

आज हमारे देश में साइबर फ्रॉड के मामले बहुत बढ़ गए हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा के लिए इन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। पर्सनल या बिजनेस का डेटा सुरक्षित रखें। अनजान लिंक को न खोलें। किसी को भी ऑनलाइन या अपने इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स न दें। केवाईसी के नाम पर भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए बैंक से संपर्क करें। आजकल तो ई-चलान, बिजली बिल भरने के नाम पर धोखाधड़ी के मैसेज आ रहे हैं, इनसे भी सावधान रहें। अपने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड और पिन बदलते रहें। हालांकि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से बचने के अनेक उपाय किए हैं, लेकिन समूह समाज को भी संवेत रहना होगा।

- मनीष अग्रवाल, धमतरी

ऑफ बीट

कैसे साफ किया जा सकता है अंतरिक्ष में मौजूद कचरा

सत्र साल पहले पृथ्वी का सिर्फ एक ही प्राकृतिक उपग्रह था- चंद्रमा। आज पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों की संख्या 15,000 से अधिक हो चुकी है, जिनमें से लगभग 10,000 एलन मस्क की कंपनी 'स्पेसएक्स' के हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क की योजना 10 लाख और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर और चौड़ाई करीब 20 मीटर होगी तथा ये मिलकर अंतरिक्ष में डेटा केंद्रों के रूप में काम करने वाला एक विशाल उपग्रह समूह बनाएंगे। अंतरिक्ष कवर से आशय पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उन सभी वस्तुओं से है, जिनका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। इनमें इस्तेमाल हो चुके रॉकेट के हिस्से, निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त उपग्रह तथा अति सूक्ष्म कण भी शामिल हैं। वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में 10 सैटीमाइटर से बड़े कचरे के करीब 36,000 टुकड़े हैं, जबकि इससे छोटे कणों की संख्या करोड़ों में है। अनुमान है कि इस पूरे मलबे का कुल वजन 13,486 टन है। इस मलबे में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका, रूस और चीन का है। अंतरिक्ष मलबा इस्लॉय बंदर खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति सैकंड की औसत गति से पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहा होता है। इतनी तेज गति से होने वाली एक टक्कर किसी उपग्रह को पूरी तरह तोड़ सकती है तथा उससे और भी अधिक अंतरिक्ष मलबा पैदा हो सकता है।

टैंड

विजया मेहता को श्रद्धांजलि

दिग्गज अभिनेत्री और शिष्टर डायरेक्टर विजया मेहता के निधन की खबर दिल तोड़ने वाली है। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि। विजया ताई ने कई नाटकों और फिल्मों के जिएए अहम योगदान दिया। - नितिन गडकरी, कैदीय राजमार्ग मंत्री



इजराइल दौरा

हम इजराइल के राजनीतिक दायरे में और गहरे धंसे जा रहे हैं, जबकि दुनिया उससे तेजी से दूर हो रही है। प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा एक हेरान्तक घटना है जो राजनीतिक फैसले के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। - राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस



नई ईवी पॉलिसी

दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर गैजट में नोटिफाई कर दिया गया है और यह अगले दो वर्षों में लागू होगी। इसमें 30,000, ई-वीएल को 50,000 और एनए केटीएल के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी। - रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली



विकास का अगला चरण

इस साल अगस्त में बिजली की अधिकतम मांग के 3,000 एलएचव्यू से ज्यादा होने की उम्मीद है, इसलिए हम राज्य को बिजली के मांगने में सफल बनाने के लिए प्रतिक्रिया देंगे। हम अगले विकास के अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं। - हिमंत बिस्वा सरमा, सीएम, असम



आपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फेसबुक : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से : hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

घटती कीमतें

अमेरिका-ईरान युद्ध के तनाव में कमी आने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट शुरू होना स्वाभाविक है। तनाव कम होने से भारत में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में 180 रुपये से अधिक की कमी आई है। होटलों और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में बुधवार को वाजिब कटौती की गई है। यह इस साल की पहली कटौती है, इसके बाद वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपये हो गई है। कीमतें और कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि फरवरी में इस सिलेंडर की कीमत 1,907 रुपये थी। जेट या विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में भी प्रति लीटर पांच रुपये की कमी की गई है, यहां भी और कमी की गुंजाइश है। सामान्य पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कमी करने में निजी कंपनी नायरा ने बाजी मार ली है। करीब 7,000 पेट्रोल पंप वाली भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनजी ने बुधवार को पेट्रोल में पांच रुपये प्रति लीटर व डीजल में तीन रुपये लीटर की कटौती कर जरूरी राहत दी है।

वैसे, मार्च में अमेरिका-ईरान युद्ध के चरम पर पहुंचते ही नायरा ने ही भारत में तेल की कीमतों में सबसे पहले इजाफा किया था। अब नायरा की ताजा पहल से सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन विक्रेता कंपनियों पर भी कीमतों को घटाने के लिए स्वाभाविक दबाव पड़ रहा है। हालांकि, कीमतों को घटाना आसान नहीं है। भारतीय सार्वजनिक पेट्रोलियम

भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनजी ने पेट्रोल की कीमतों में सबसे पहले इजाफा किया था और अब उसी ने कीमतों को सबसे पहले घटाया है।

कंपनियां फिलहाल अपने घाटे को दूर करने में लगी हैं। यह बात सही है कि भारत में बहुत देर से कीमतों में वृद्धि की गई थी। भारत ऐसे विरल देशों में शुमार था, जहां सामान्य पेट्रोल, डीजल को महंगा नहीं किया गया था। बाद में वृद्धि तब की गई, जब दुनिया के अनेक देश कीमतों में कटौती कर रहे थे। चीन ने तो अप्रैल में ही कीमतों को घटाना शुरू कर दिया था। यह सही है कि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ईरान ने भी आपूर्ति बढ़ाई है और रूस ने भी निर्यात में इजाफा किया है। इन दोनों ही देशों को धन की

बहुत जरूरत है। हालांकि, यहां से कच्चे तेल की कीमतों में और कमी नहीं आएगी। 128 फरवरी को जंग ईरान पर हमला हुआ था, उससे पहले विश्व बाजार में तेल की कीमत 68 डॉलर प्रति बैरल थी और कीमतें एक समय 100 डॉलर के पार चली गई थीं। अतः अब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी कीमतों को घटाने की मांग हो रही है। अमेरिका में तो स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कंपनियों को कीमत में कटौती के लिए एक तरह से धमकाया है। एक समय अमेरिका में तेल की कीमत 4.48 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गई थी और अब वहां कंपनियों ने कीमतों में कमी की है, कीमतें 3.86 डॉलर पर आ गई हैं, जबकि ट्रंप ने कंपनियों से कहा है कि कीमत को 2.50 डॉलर पर लाया जाए। वैसे, युद्ध से पहले अमेरिका में कीमत 2.98 डॉलर थी। व्यावसायिक दुनिया में आमतौर पर यही होता है, पेट्रोलियम कंपनियों कीमतों में इजाफा तो कर देती हैं, लेकिन कीमतों को घटाने में उन्हें बहुत जोर आता है। भारत की जहां तक बात है, पेट्रोल की कीमतों को फिर 100 रुपये के नीचे लाना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। ध्यान रहे युद्ध से पहले फरवरी के महीने में भारत में महंगाई दर 3 प्रतिशत से भी नीचे थी, लेकिन मई में 4 प्रतिशत के पार बढ़ने लगी थी। जुलाई और अगस्त के लिए तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं, पर अब राहत का एहसास हो रहा है। अब अगर पेट्रोल, गैस की कीमतों में जरूरी कमी की जाएगी, तब व्यापकता में आम लोग महंगाई से राहत महसूस करेंगे।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले

02 जुलाई, 1951

फलदार पेड़ लगाएं

भारत सरकार के खाद्य-मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी ने द्वितीय वन-महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाने की देशवासियों से अपील की है। हम बिना किसी संकोच के इस अपील का समर्थन करते हैं। आज से ही यह उत्सव प्रारंभ हो रहा है और 15 अगस्त तक इसे जारी रखना होगा। इस उत्सव का मुख्य लक्ष्य यह है कि देश में कम से कम तीन करोड़ नये वृक्षों का रोपण किया जाये। उनमें से कम से कम एक करोड़ फलों के वृक्ष होने चाहिए। वृक्षों के रोपण के लिए वर्षा का मौसम सबसे अधिक उपयुक्त होता है और इसीलिए यह समय इस उत्सव के लिए चुना गया है। गत वर्ष भी देश में वन-महोत्सव मनाया गया था और तीन करोड़ वृक्ष लगाये गये थे। उनमें से एक करोड़ पौधे सुरक्षित रह सके हैं। यदि ये अंक सही हैं, तो मानना होगा कि गत वर्ष का प्रयास बड़ी हद तक सफल रहा। उत्सव का लक्ष्य समाज में एक विशेष भावना जागृत करना है। लोगों का ध्यान एक विषय पर केंद्रित हो जाता है। इस दृष्टि से वृक्षारोपण के प्रदर्शनों का महत्व है। उन्हें अर्थहीन नहीं समझा जा सकता। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वृक्षारोपण के प्रदर्शनों के साथ ही हमारे दीर्घकालिक इतिहास को न होना चाहिए। जो नये वृक्ष लगाये जायें, उनके संवर्द्धन के लिए दीर्घकालिक की आवश्यकता होती है।

अतः वृक्षारोपण के लिए लोगों में क्षणिक जोश उत्पन्न होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमारा वन महोत्सव मानना उसी अवस्था में सार्थक होगा, जब रोपित वृक्षों के नन्हे पौधों को हम अपनी सतत देख-भाल द्वारा अपने पांवों पर खड़ा करें। जब हम ऐसा करने लगेंगे, तो फिर उस आरोप के लिए कोई स्थान नहीं रह जायेगा कि वन-महोत्सव के पीछे कोरी प्रदर्शन भावना है। उस दशा में हम वन-महोत्सव को ठोस आधार प्रदान कर देंगे।

हमें अपने देश को अन्न स्वावलंबी बनाना है। भारत सरकार ने तो अपना यह लक्ष्य स्थिर कर लिया था कि वह मार्च 1952 के बाद विदेश से अन्न का आयात नहीं करेगी। विदेश से अन्न का आयात वह उत्तरोत्तर कम करती जा रही है, किन्तु प्रकृति ने अचानक हमारी योजनाओं को व्यर्थ कर दिया। अनावृष्टि और अतिवृष्टि ने देश के कुछ भागों में अन्न की फसलों को चौपट कर दिया और हमें अन्न के लिए विदेश के द्वार खटखटाने पड़े।

को बचाने के लिए चिपको आंदोलन आरंभ कर दिया था। अगर हमारे पूर्वजों ने पौधे न लगाए होते, वृक्षों को घड़ाघड़ सिर्फ काटा होता, तो क्या आज हमें वृक्षों से मिलने वाला सुख प्राप्त होता? शायद नहीं। इसी तरह, आज हम यदि पर्यावरण को संभालने के लिए गंभीर नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो क्या आने वाली पीढ़ी को हम साफ-सुथरा पर्यावरण दे सकेंगे? शायद नहीं।

बरसात के मौसम में अगर पौधे लगाए जाएं, तो वे बहुत अच्छे तैयार होते हैं, क्योंकि उनको भरपूर पोषण मिलता है। इसलिए जिन घरों में पौधे लगाने की जगह है, वहां एक पौधा तो जरूर लगाएं। हालांकि, बरसात के मौसम में कुछ राज्य सरकारें अपने यहां पौधे लगाने के लिए विशेष अभियान चलाती हैं, समाजसेवी संस्थाएं और अन्य लोग भी इसके लिए काम करते हैं। आमजन को जहां जगह हो,

पेड़ लगाने चाहिए। सड़कों या रेल लाइनों के विस्तार के लिए यदि पेड़ों को काटने की मजबूरी हो, तो वहां नए पौधे लगाने की व्यवस्था की जाए, बल्कि पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी देख-रेख भी की जाए। उष्ण कटिबंधीय वनों पर हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कुल्हाड़ी चल रही है। कुल्हाड़ियों वनों पर नहीं, बल्कि हमारे सुखद जीवन पर भी चल रही हैं, क्योंकि वनों के काटने से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए हानिकारक है। वन हैं, तो हम हैं। जो वृक्ष हमें फल नहीं देते हैं, वे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बिना किसी मूल्य के देते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि अब वनों के संरक्षण में लापरवाही बरती जा रही है।

राजेश कुमार चौहान, टिपणीकार

वनों से ही हमारा आज और कल सुरक्षित

हमारे जीवन में वनों का बहुत महत्व है। वन की अधिकता से हमारा पर्यावरण संरक्षित होता है और इससे मानव जीवन को प्राण वायु शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हमारे देश में 7 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा और उनकी कटौती से जीव-जंतुओं पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता फैलाना भी है।

भारत में आजादी के तुरंत बाद ही वनों और वृक्षों को काटने से रोकने के प्रयास सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा आरंभ कर दिए गए थे। एक तरफ वनों, 1950 में वनों को बचाने के लिए 'वन महोत्सव' की शुरुआत की गई, वहीं दूसरी तरफ 1970 के दशक में जब देश में वन संपदा का अवरण भंडार था, तब भी पर्यावरण की चिंता करते हुए यहवाक्य के लोगों ने वृक्षों

को बचाने के लिए चिपको आंदोलन आरंभ कर दिया था। अगर हमारे पूर्वजों ने पौधे न लगाए होते, वृक्षों को घड़ाघड़ सिर्फ काटा होता, तो क्या आज हमें वृक्षों से मिलने वाला सुख प्राप्त होता? शायद नहीं। इसी तरह, आज हम यदि पर्यावरण को संभालने के लिए गंभीर नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो क्या आने वाली पीढ़ी को हम साफ-सुथरा पर्यावरण दे सकेंगे? शायद नहीं।

बरसात के मौसम में अगर पौधे लगाए जाएं, तो वे बहुत अच्छे तैयार होते हैं, क्योंकि उनको भरपूर पोषण मिलता है। इसलिए जिन घरों में पौधे लगाने की जगह है, वहां एक पौधा तो जरूर लगाएं। हालांकि, बरसात के मौसम में कुछ राज्य सरकारें अपने यहां पौधे लगाने के लिए विशेष अभियान चलाती हैं, समाजसेवी संस्थाएं और अन्य लोग भी इसके लिए काम करते हैं। आमजन को जहां जगह हो,

पेड़ लगाने चाहिए। सड़कों या रेल लाइनों के विस्तार के लिए यदि पेड़ों को काटने की मजबूरी हो, तो वहां नए पौधे लगाने की व्यवस्था की जाए, बल्कि पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी देख-रेख भी की जाए। उष्ण कटिबंधीय वनों पर हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कुल्हाड़ी चल रही है। कुल्हाड़ियों वनों पर नहीं, बल्कि हमारे सुखद जीवन पर भी चल रही हैं, क्योंकि वनों के काटने से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए हानिकारक है। वन हैं, तो हम हैं। जो वृक्ष हमें फल नहीं देते हैं, वे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बिना किसी मूल्य के देते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि अब वनों के संरक्षण में लापरवाही बरती जा रही है।

राजेश कुमार चौहान, टिपणीकार



संजय कुमार भारद्वाज | प्रोफेसर, जेएनयू, दिल्ली

फरवरी 2026 में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया और चीन को चुना। पहले वह मलेशिया गए, इसके बाद वह चीन पहुंचे। रहमान का यह चयन तीन राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा है। पहली, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन; दूसरी, मुखर भारत-विरोधी भावनाएं; और तीसरी, अवामो लोग की राजनीति से खुद को अलग दिखाने की परंपरागत नीति।

सत्तारूढ़ बीएनपी की विदेश नीति पहले से इस्लामी जगत व चीन के करीब रही है। भारत सरकार ने फरवरी में ही प्रधानमंत्री रहमान को नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन बीजिंग को प्रार्थमिकता देना यह संकेत है कि बीएनपी अपनी परंपरागत विदेश नीति को जारी रखना चाहती है। खासकर शेख हसीना के बाद, जब दोनों देशों के संबंध अवशिवास, उभरते द्विपक्षीय मुद्दे और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा के दौर से गुजर रहे हैं।

दरअसल, शेख हसीना सरकार के विरुद्ध आंदोलन और सत्ता-परिवर्तन के बाद भारत को लेकर बांग्लादेश में माहौल बदला हुआ है। ऐसे में, तारिक रहमान पर यह दबाव है कि वह खुद को शेख हसीना की राजनीति से अलग दिखाएं। जमात-ए-इस्लामी और दूसरे मजहबी समूहों का दबाव भी बीएनपी सरकार पर है। अतः इन ताकतों को संतुलित करने की चुनौती भी है। बीएनपी ने अपनी 'सॉफ्ट इस्लामपरस्ती' की नीति पर पुनर्र लाने के लिए सबसे पहले मुस्लिम-बहुल देश मलेशिया को चुना। बीएनपी की विदेश नीति उनके पिता जियाउर रहमान के दौर से ही इस्लामी दुनिया के करीब रही है।

सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुधारने की कोई ठोस प्रष्टुभूमि तैयार हुई है? रिश्ते सामान्य करने के लिए दिसंबर 2025 में खालिदा अनिस के अंतिम संस्कार के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए। रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम वरिन्दा पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी का

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को लेकर इतना सन्नाटा क्यों

भारत-नेपाल संबंधों को अक्सर 'रोटी-बेटी' के रिश्ते के रूप में देखा जाता है। यह सिर्फ कूटनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सदियों से विकसित सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक भी है। यहां सीमाएं मगर नक्शों पर खिंची रेखाएं प्रतीत होती रही हैं, लेकिन इस आत्मियता के बीच एक ऐसा सन्नाटा भी मौजूद है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण राज्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में पसर है। यह हमारी संप्रभुता, सीमा-प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर प्रश्नों को सामने लाता है।

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 70 से अधिक बाघों का बसेरा है, मगर इस अभयारण्य के सीमावर्ती इलाके के सुरक्षा और चकदहवा क्षेत्र लंबे समय से विवाद के केंद्र में हैं। विभिन्न प्रशासनिक आकलनों के अनुसार, इसकी लगभग 5,478 एकड़ भूमि पर नेपाल दावा करता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मौन रहा है। इतिहासिक की जड़ें सन् 1814 से 1816 के बीच हुए आंग्ल-नेपाल युद्ध और उसके बाद हुई सुगौली संधि में निहित हैं। 1815 में हस्ताक्षरित और 1816 में प्रभावी हुई इस संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के बीच सीमा निर्धारण की आधारशिला रखी। राप्ती व गंडक नदियों के बीच के तराई क्षेत्र का पुनर्समीकरण हुआ और गंडक नदी को सीमा का आधार माना गया।

प्रकृति किसी राजनीतिक नक्शे का सम्मान नहीं करती। नदियां अपने प्रवाह बदलती हैं, नए रास्ते बनाती हैं और पुराने मार्ग छोड़ देती हैं। गंडक नदी की धारा में भी परिवर्तन हुआ और उसके पुराने तथा नए प्रवाह के बीच स्थित भूमि की स्थिति जटिल होती चली गई। यहीं से प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि सीमा नदी की वर्तमान धारा से तय होगी या उस ऐतिहासिक धारा के अनुसार, जिसे सुगौली संधि के समय आधार माना गया था?

सन् 1964 में यह विवाद गंभीर रूप में सामने आया। वाल्मीकिनगर में गंडक सिंचाई परियोजना के शिफ्टाव्यय के दौरान सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ा और रमपुरवा में भारतीय प्रांतीयों ने नेपाल की शाही सेना के बीच हिंसक झड़प हुई। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी कि सीमा के पुनः सीमांकन तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नए निर्माण पर रोक व पुलिस बल की तैनाती जैसे निर्णय भी लिए गए, पर समय बीतने के साथ ये निर्णय फाड़लौ तक सिमट गए।

आज स्थिति बदल चुकी है। जीपीएस आधारित



अमरेंद्र किशोर | वरिष्ठ पत्रकार

आकलन के अनुसार, लगभग 3.75 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में दर्जनों पक्के मकान और स्थायी बसाहट मौजूद है। वन भूमि के अतिक्रमण के कारण राज्य सरकार को वन संपदा के बड़े नुकसान का अनुमान है। नरसही जंगल जैसे क्षेत्र इस विवाद की सीधी मार ले रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के महत्वपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है और यह अनेक वन्य जीवों, विशेषकर बाघों को रिहाइश प्रदान करता है। ऐसे में, सीमाई अनिश्चितता का प्रभाव अन्य वन्य जीवों की प्रशासनिक देखभाल पर तो पड़ता ही है, पारिस्थितिकी पर भी पड़ रहा है। सुल्ला क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण भारत का है, जबकि नेपाल ऐतिहासिक व संघगत आधार पर अपना दावा पेश करता है और उसे अपने नवलपरासी क्षेत्र का हिस्सा बताता है। भारत का तर्क है कि सीमा निर्धारण नदी की वर्तमान धारा के आधार पर होना चाहिए, वहीं नेपाल 1816 की संधि के समय की नदी धारा

को आधार मानता है। भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत भाग निर्धारित हो चुका है, पर सुरक्षा व कालापानी जैसे क्षेत्र आज भी लंबित हैं। सुरक्षा में रहने वाले लोगों के लिए यह विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न नहीं, बल्कि खेत, जंगल व पहचान पर टुकड़ा जंगम का यथार्थ है। हालांकि, जमीनी स्तर पर जुद्धाव्यय की स्थिति नहीं है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर सक्रिय हैं और कूटनीतिक संवाद का प्रक्रिया भी जारी है।

फिर भी, अंतिम समाधान अभी दूर है। जब तक सीमा का स्पष्ट, पारदर्शी और परस्पर स्वीकार्य सीमांकन नहीं हो जाता, तब तक यह विवाद नए-नए रूपों में सामने आता रहेगा। वक्त आ गया है कि इस सन्नाटे को दूरदृष्टि, संवेदनशीलता व ठोस संकल्प के साथ तोड़ा जाए, ताकि सीमाएं नक्शों के साथ-साथ जमीन पर भी स्पष्ट, सुरक्षित और निर्विवाद रूप से स्थापित हो सकें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)



अनुलुम-विलोम वन महोत्सव



दिखावे के उत्सवों से किसी का भला नहीं

हमारे देश में वन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सरकारी समर्थन मिलने के कारण इसका रुतबा और ज्यादा बढ़ जाता है। पूरे सप्ताह तक मनाए जाने वाले इस समारोह में राष्ट्रीय स्तर के राजनेता, सरकारी अधिकारी से लेकर गांव की पंचायत तक के सरकारी कर्मचारी और जन-प्रतिनिधि शामिल हो जाते हैं। इनके समारोहों में उत्साह से शामिल होने वाले फोटो देखकर आप इस मलफत में न फंस जाएं कि ये वनों, वृक्षों के प्रति बेहद संवेदनशील लोग हैं या देश में वनों की दुर्दशा देखकर ये सब बेहद चिंतित हैं।

वन महोत्सव हमारे देश में जिस जोर-शोर से मनाया जाता है, वास्तविकता वैसी नहीं है। केवल एक सप्ताह के दिखावटी पौधारोपण और सरकारी आयोजनों को देखकर इसे अक्सर ढकोसला मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें कोसला आंकड़ों पर अधिक और असली देखभाल पर कम

ध्यान दिया जाता है। वास्तविक धरातल पर इसके विफल रहने की वजह है, उचित देखभाल के अभाव में पौधों का मर जाना। पौधे लगाने के बाद उनकी उचित सार-संभाल या पानी देने की व्यवस्था नहीं होती। अक्सर महोत्सव के दौरान लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में नियमित सिंचाई और सुरक्षा न होने से वे सूख जाते हैं। इन पौधों को अनियोजित तरीके से लगा दिया जाता है। बिना यह सोचे कि स्थानीय जलवायु और मिट्टी के लिए कौन सा पेड़ उपयुक्त है, अंधाधुंध पौधे लगा दिए जाते हैं और उसके साथ फोटो खिंचकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली जाती है। गिनती के लिए बड़ी संख्या में गलत प्रजाति के पौधे लगा देना भी इनके नष्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह अक्सर यह उत्सव राजनेताओं, अधिकारियों और कुछ संस्थाओं के लिए 'पब्लिसिटी स्टेट'

बनकर रह जाता है। इसके अलावा इस तरह के प्रचारात्मक अभियानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धोर अभाव होता है। कागजों पर वृक्षारोपण का भारी लक्ष्य दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पर पुरानी लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई की तुलना में नए पेड़ पनप नहीं पाते। इस तरह की गैरजरूरी शोशेबाजी से हमें बचने की जरूरत है। हमें पौधारोपण कार्यक्रम के क्रियाव्यवधान में सुधार करने की आवश्यकता है। यह केवल पेड़ लगाने का नहीं, बल्कि वृक्ष बचाने तक उनकी संरक्षित करने का संकल्प लेना का अक्सर है। अगर इसे सिर्फ एक उत्सव के आयोजन तक सीमित न रखकर पूरे साल पौधों के जीवित रखने पर ध्यान दिया जाए, तभी यह सार्थक किर्तय बन सकता है, अन्यथा वर्तमान स्थिति में तो यह सारा क्रियाकलाप ढोल की पील जैसा है।

अपूर्व कोशल, छात्र

बांग्लादेश की नई राजनीति पर नजरें टिकी हुई हैं। भारत नहीं चाहता कि उसके पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास चीन को ऐसी भू-राजनीतिक पकड़ मिले, जिसका कमी सामरिक इस्तेमाल हो।



प्र उन्हे सौपा था। उस पत्र में रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी अप्रैल में भारत आए।

दोनों देशों के बीच चार बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, भारत ने करीब दो साल बाद 28 जून, 2026 से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर से पर्यटक वीजा जारी करना शुरू किया है। पहले ही दिन करीब 1.4 लाख आवेदन आए। मॉडकल और आपात वीजा सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। युनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंदवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती

दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। युनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंदवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती

दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। युनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंदवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती

दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। युनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंदवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती

दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। युनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंदवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती

दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। युनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंदवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती

दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। युनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंदवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती

दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। युनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंदवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती

दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का

दैनिक जागरण

निरंतर अभ्यास से ही कौशल का विकास संभव है

बेलगाम होता भ्रष्टाचार

सीबीआई की ओर से तीन करोड़ रुपये की रिश्तखोरी के मामले में आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत की गिरफ्तारी प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर फिर से ध्यान आकर्षित कर रही है। दीपक गहलावत को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, वह नकली दवा बनाने वाले वैकेंट की जांच से जुड़ा है। इस रिश्तखोरी कांड के समय गहलावत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये की रिश्तखोरी के बदले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नकली दवा बनाने के आरोपित कारोबारी को सीबीआई जांच से बचाने का भरोसा दिया। उन्होंने जांच एजेंसी के अधिकारियों पर इसके लिए दबाव भी बनाया। कहना कठिन है कि इस मामले की तह तक पहुंचने और दीपक गहलावत को उनके किए की सजा दिलाने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन यह एक तरह से बाढ़ खेत को खाए वाला एक और मामला है। यह लगातार देखने में आ रहा है कि रह-रह कर ऐसे अधिकारी सामने आते ही रहते हैं, जो गंभीर क्रिमि के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी होती है और उनके पास से अकूल संपत्ति भी बरामद होती है, लेकिन वह बहुत कम सुनने को मिलता है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया गया।

भ्रष्ट अधिकारियों को समय रहते दंड न दिए जाने का परिणाम यह है कि उनका भ्रष्टाचार बेलगाम है। कुछ मामले तो ऐसे सामने आते हैं, जो खुले-गमन भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाई और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाले का है। यह घोटाला 650 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। वास्तव में यह घोटाला नहीं एक तरह की खुली लूट थी। इसे इससे समझा जा सकता है कि बिना जरूरत कई गुना महंगे दवाओं पर दवाई और मेडिकल उपकरण खरीदे गए। ऐसा लगता है कि किसी को नियम-कानूनों की कहीं कोई परवाह नहीं थी। इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डा. वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले में किस तरह करोड़ों के बरे-न्यारे किए जा रहे थे, यह इससे समझा जा सकता है कि 650 करोड़ रुपये में से करीब 50 प्रतिशत भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों की जेब में गए। नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक नासूर बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दलों के बाद भी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर कहीं कोई प्रभावही लगाम लगती नहीं दिखती। भ्रष्ट नौकरशाही केवल सरकारी खजाने को लूटने का काम ही नहीं कर रही है, वह आम लोगों की समस्याएं बढ़ाने का भी काम कर रही है, क्योंकि जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उससे कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता भी होता है।

किसानों की आय

मानसून की प्रकृति में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष खेती-किसानी में बदलाव आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि को केवल मौसम की अनिश्चितताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित जलवायु अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणाली को उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में लागू किया जा रहा है, जिससे कम वर्षा होने पर भी किसानों का उत्पादन और आय प्रभावित न हो। किसानों को आधुनिक और जलवायु-अनुकूल खेती का प्रशिक्षण देने तथा आय के विविध स्रोत विकसित करने की यह पहल स्वागतयोग्य है। दरम्यान जलवायु परिवर्तन का किसानों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है। वर्षा का समय और मात्रा में परिवर्तन से किसानों की आय

प्राकृतिक आपदाओं के बीच किसानों की आय की बेहतर सुरक्षा समय की मांग है

और ख़ाब सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। कहीं अत्यधिक बारिश से फसलें डूब जाती हैं, तो कहीं सूखे से बोआई प्रभावित होती है। कृषि ब्रानिची, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों के प्रति आधुनिक कृषि तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदेश के किसानों के लिए वैकल्पिक आय का साधन बनेगा। इन सबके बीच एक अच्छी बात यह है कि तीन वर्षों तक इसके लिए शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ऐसा होने से किसानों की आय को बढ़ाने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। इस परिकल्पना को सफलता के लिए आवश्यक है कि किसानों के बीच वैकल्पिक आय के साधन को प्रोत्साहित करने वाली इस पहल के प्रति विश्वास पैदा हो।



अलोक रंजन

समय पर न्याय मिलना ही वह मानक है, जिसकी नगारिका उम्मीद करते हैं। भारतीय न्याय संहिता में सुधार इसी को ध्यान में रखकर किए गए हैं

एक आम नागरिक के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली केवल कानूनों, नियमों या संस्थाओं का कोई संग्रह नहीं है। वह इसका अनुभव कुछ सीधे और सरल सवालों के माध्यम से करता है। जैसे क्या शिकायत तुरंत दर्ज की गई? क्या जांच के दौरान पीड़ित को हर बात की जानकारी दी गई? क्या साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया गया? क्या गवाह को समय पर समन मिला? और क्या मामला बेवजह की देरी के बिना समाप्त हुआ? इन सवालों के जवाब तलाशें तो पाएंगे कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली लंबे समय से दोहरे बोझ से जूझ रही है। एक तो पूरी प्रक्रिया देश की शिकायतों है और दूसरे उसमें इतना बिखराव है कि बात बनते-बनते रह जाती है। एक बड़ी संख्या में मामलों आपस में कटी हुई संस्थाओं, कागजी कामकाज के भारी बोझ और अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों के असमान तौर-तरीकों से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि पूरी व्यवस्था पीड़ित-केंद्रित होने के बजाय प्रक्रिया-केंद्रित बनकर रह जाती है। इस क्रम में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) बड़ी क्रांतिकारी पहल हैं। एक जुलाई, 2024

से लागू यह व्यवस्था पुराने ढर्रे को बदलने का प्रयास है। इनका उद्देश्य केवल पुराने कानूनों को बदलना नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस और पीड़ित-केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करना है। न्याय संहिता के तहत सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में एक है जांच और न्यायिक सुनवाई के दौरान 45 अतिरिक्त सुनियोजित समय-सीमाएं तय करना, जिससे अब कुल समय-सीमा की संख्या 145 हो गई है। इसका उद्देश्य किसी मामले के आरंभ से लेकर उसके अंतिम फैसले तक की पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तीन वर्ष के भीतर पूरा करना है। महत्वपूर्ण यह है कि ये निर्धारित समय-सीमाएं केवल कागजी घोषणाएं नहीं हैं। इन्हें आपराधिक न्याय के डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से तकनीक-आधारित निगरानी प्रणालियों का पूरा समर्थन हासिल है। अब जांच अधिकारियों के लिए स्वचालित अलर्ट जेनरेट होते हैं, ताकि आरोप पत्र समय पर दाखिल करना सुनिश्चित किया जा सके। न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न चरणों में समय-सीमा की निगरानी करने में सहायता के लिए कोर्ट के केस-मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म 'यानि' केस इन्फार्मेशन सिस्टम' में भी इसी तरह की समय-सीमाएं जोड़ी जा रही हैं। इसके



अवधेश राजगुप्त

पीछे का मूल सिद्धांत बेहद सरल है 'समय-सीमा और तकनीक मिलकर विश्वास पैदा करते हैं।' जांच की समय-सीमा की ऐसी निगरानी से आरोप पत्र दाखिल करने के अनुपालन में काफी सुधार हुआ है: 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की दर 2024 के 51 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 67 प्रतिशत हो गई है, जबकि इसी अवधि में 90 दिनों के भीतर अनुपालन की दर 40 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। इन सुधारों का दूसरा स्तंभ है कि इसमें टेक्नोलॉजी का एकीकरण सिर्फ डिजिटलीकरण के लिए नहीं, बल्कि आपरेेशनल प्रेमवर्क के तौर पर किया गया है। इससे कई सुधारों की राह खुली है। जैसे ई-एफआइआर (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन्फार्मेशन रिपोर्ट), जीरो-एफआइआर (जो अधिकार-क्षेत्र और भाषा की सीमाओं से परे है), ई-साक्ष्य (इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रीकरण और उनका प्रबंधन), ई-समन (समन जारी कर उन्हें पहुंचाना), मेडिको-लीगल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, ई-फोरेंसिक्स, ई-प्रिजंस, ई-प्रोसेक्यूशन और न्यायिक कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये

सभी पेपरलेस और एकीकृत इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जहाँ डिजिटल रूप से प्रमाणित रिकार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डाटा साक्षात्करण द्वारा प्रक्रियाएं तेज और अधिक पारदर्शी बनती हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का विस्तार है। यह व्यवस्था 'वन डाटा, वन प्रूटी' यानी एक बार डाटा और एकल प्रविष्टि के दृष्टिकोण के तहत आपराधिक न्याय के पांच स्तंभों- पुलिस, अदालत, कारावास, फोरेंसिक और अभियोज्य को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपस में जोड़ती है। पुलिस और अदालतों के बीच प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र के लगभग रियल-टाइम इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान से काम के दोहराव की आशंका घटी है। डाटा की सटीकता के चलते अशिक्षित सुधार संभव हुआ है, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। आपराधिक मुकदमों में समन की तामील एक बड़ी अड़चन रही है। अब इस पूरी प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया संभव हुआ है। याद रहे कि कोई भी न्याय प्रणाली साक्ष्यों की गुणवत्ता से ही मजबूत होती है।

चीन प्लस-वन का विकल्प बनता यूपी

कि सी राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब एक अकेला निर्णय न केवल भूगोल को, बल्कि समूची नियति को बदल देता है। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और व्यावसायिक उड़ानों का शुभारंभ निःसंदेह ऐसा ही एक क्षण है, लेकिन इसे केवल एक हवाई अड्डा कहना भूलेंगे। भू-अर्थशास्त्र की दृष्टि से जेवर महज एक अवसरचरणा नहीं, एक घोषणापत्र है, जो भूगोल, आर्थिक शक्ति और भू-राजनीतिक रणनीति का संगम है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो सदियों से अपनी भूबद्ध स्थिति को बेड़ियों में जकड़ा रहा, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के द्वार पर दस्तक दे रहा है। 24 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य जनसंख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी उप-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, लेकिन समुद्री व्यापार मार्गों तक उसकी सीधी पहुंच नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डा उद्घाटन के अवसर पर इसी संचारों को रेखांकित किया कि यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की भूबद्ध बाधाओं को तोड़कर राज्य के एमएसएमई, कृषि और भारी उद्योगों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। जेवर की श्रीरक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने जो कहा, वह भू-आर्थिक सोच का संक्षिप्त सार है कि यह सिर्फ एक हवाई अड्डा ही नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक विकास का प्रवेश द्वार है।



इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जब कहीं उड़ान पट्टी तैयार होती है, तो प्रगति के स्वप्न भी तेजी से उड़ान भरते हैं



विकास की मजबूत कड़ी बनेगा जेवर हवाई अड्डा। फाइल

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 3,706 करोड़ रुपये का एचसीएल-फाक्सकान सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम नोएडा से जेवर तक यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक नए औद्योगिक हब की नसों हैं। वाईआईआईपी को एफडीआई और फार्च्यून्-500 नीति के तहत आठ कंपनियों ने इस गलियारे में 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। सेमीकंडक्टर संयंत्र का महत्व विश्वीय रूप से रेखांकित करने योग्य है। यहाँ बनने वाली चिप मोबाइल फोन, लैपटॉप और आटोमोबाइल को संचालित करेंगी, वहीं उत्पाद जो वैश्विक चीन-प्लस-वन आपूर्ति श्रृंखला पुनर्रिक्लिंग के केंद्र में हैं। नोएडा में सैमसंग का विश्वस्तरीय विनिर्माण केंद्र, हैबेल्स, अंबर एंटरप्राइजेज, माइक्रोसाफ्ट और एचसीएल-फाक्सकान की उपस्थिति से यह गलियारा उत्तर भारत में चीन-प्लस-वन रणनीति का प्राथमिक केंद्र बन चुका है। कार्गो हब का लक्ष्य है कि भारत को, विशेषकर उसके उत्तरी क्षेत्र को, वैश्विक लाजिस्टिक्स का प्रमुख प्रवेशद्वार और चीन-प्लस-वन रणनीति का विश्वसनीय

विकल्प बनाया जाए। भारत के पहले एकीकृत एमआरओ केंद्र के रूप में भी जेवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। दशकों से भारतीय एयरलाइंस विमानों के रखरखाव के लिए सिंगपुर और दुबई पर निर्भर रही हैं। जेवर कृषि के लिए भी उतना ही क्रांतिकारी है। फल, सब्जियाँ, दुग्ध उत्पाद और सजावटी फूल अब सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे। इससे किसानों की आय में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर जेवर मेक इन इंडिया, उत्पादन-लिंकव प्रोत्साहन और राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स नीति तौरों को एक साथ गति देता है। 50,000 प्रत्यक्ष और 50 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार, फिल्म सिटी, रिलीनो पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और डाटा सेंटर का पूरा इकोसिस्टम आज उत्तर प्रदेश और एनसीआर को एक नई वैश्विक पहचान दे रहा है। जेवर हवाई अड्डा एक दिन में नहीं बना है, यह अथक भूमि अधिग्रहण, नीतिगत नवाचार, निवेशक कुटनीति और दूरदर्शी राजनीतिक साहस का संमिश्रित परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब शासन की बागडोर संभाली थी तब उत्तर प्रदेश देश के तीन सबसे पिछड़े राज्यों में था। आज राज्य को 50 लाख करोड़ रुपये के संघीय निवेश प्रस्ताव मिले हैं। पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2016-17 के 71,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में देश में सर्वाधिक 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को पांच लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश भी एक लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेता है।' यह केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, एक सभ्यतागत संकल्प है। जेवर उस संकल्प का उदाहरण पट्टी है। इतिहास साक्ष्य है कि-जब उड़ान पट्टी तैयार होती है, तो स्वप्न भी उड़ान भरते हैं। (लेखक जैपन्यु में एसीरिएट प्रोफेसर हैं) response@jagran.com



अंतर्मन का प्रेम
प्रेम को प्रायः सुखद अनुभूतियों और मधुर संवेदनाओं के कोमल संगम को सीमाओं से ही समझा जाता है, किंतु उसकी वास्तविक प्रकृति इससे कहीं अधिक गहन, जटिल और बहुआयामी होती है। प्रेम की अवस्था में मनुष्य अपने अहं के सीमित दायरे से बाहर निकलकर निश्चिंतताओं का स्वेच्छा से त्याग करता है। यह समर्पण दुर्बलता का सूचक नहीं होता, बल्कि मनुष्य को उसके आंतरिक सत्य के अधिक निकट ले जाता है। प्रेम व्यक्ति को स्वयं का लोप करने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक रूपान्तरण और चेतना के विस्तार के लिए प्रेरित करता है, जहाँ उसका अस्तित्व किसी अन्य के साथ जुड़कर जीवन के व्यापक अर्थों को समझने लगता है। खलील जिब्रान ने यथार्थ ही कहा है, 'प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली है।'
प्रेम अनेक विरोधाभासों को भी समेटे रहता है। यह आनंद का स्रोत है, परंतु पीड़ा एवं विरह का अनुभव भी करता है। निकटता ही अपनत्व और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि दूरी घैर्य, विश्वास और सहनशीलता का संस्कार देती है। ये परस्पर विरोधी स्थितियाँ प्रेम को कमजोर नहीं करतीं, बल्कि उसे परिपक्व एवं स्थायी बनाती हैं। प्रेम ही सिखाता है कि सुख-दुःख, मिलन-विरह, ये सभी जीवन के अनिवार्य आयाम हैं।
प्रेम की वास्तविक शक्ति व्यक्ति की अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करने में निहित होती है। जब मनुष्य अपनी अपूर्णताओं सहित स्वयं को प्रस्तुत करने का साहस करता है, तब प्रेम बाह्य आईडल से ऊपर उठकर सच्चा और गहरा बनता है। अंशम अज्ञात को और बढ़ने का साहस देता है, जहाँ अनिश्चितता के साथ अनंत संभावनाएं भी विद्यमान होती हैं और यही प्रेम मनुष्य के आत्मा को उसके प्रकाश तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।
कुमार नृपेंद्र

लंबी उम्र के राज से उठ सकता है पर्दा

प्रदीप

विज्ञान एक लंबे असें से इस सवाल का जवाब ढूँढने में जुटा हुआ है कि दीर्घायु का रहस्य हमारे जीनों में छिपा है या फिर इसका संबंध हमारी जीवशैली से है? हाल ही में ब्राजील से आई एक खबर ने इस सवाल को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ब्राजील की तीन शतायु बहनों, लेबिटा डी डियस नुनेस (109 साल), जोराइडे (104 साल) और जुलिया डी डियस नुनेस (103 साल) विज्ञानियों के लिए जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। इतनी ज्यादा उम्र तक पहुंचकर भी उनका अपेक्षाकृत स्वस्थ और सक्रिय बने रहना शोधकर्ताओं के लिए एक जीवित प्रयोगशाला जैसा है। इन बहनों का अध्ययन विज्ञानियों को यह समझने में मदद कर सकता है कि आखिर कुछ लोग सौ साल से ज्यादा उम्र में भी शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से सेहतमंद कैसे बने रहते हैं।
ब्राजील की साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की विज्ञानी मयाना जैट्ट के नेतृत्व में चल रहा 'डीएफए लॉगेजो प्रोजेक्ट' इसी

अधिक आयु का राज 'जीन ब्राना जीवनशैली' का ढंढ नहीं, अपितु दोनों के मध्य जटिल संवाद का परिणाम है

सवाल का जवाब खोजने में जुटा हुआ है। इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे आनुवंशिक (जेनेटिक) कारकों की पहचान करना है जो उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। विज्ञानी खास तौर पर उन 'प्रोटेक्टिव जीनों' को तलाश कर रहे हैं जो शरीर को उम्र-संबंधी क्षरण से बचाते हैं, जैसे- हृदय को मजबूत रखने, मांसपेशियों की कार्यक्षमता बनाए रखने और मस्तिष्क को संज्ञानात्मक विकृति से बचाने वाले जीन।
आनुवंशिकों का प्रभाव सूक्ष्म लेकिन गहरा होता है। हमारे जीन यह निर्धारित करते हैं भूमिका निभाते हैं कि कोशिकाएं क्षति की मरम्मत कितनी कुशलता से करेंगी, सूजन कितनी तेजी से बढ़ेगी और आकसेडेटिव स्ट्रेस का शरीर पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

विज्ञानियों का मानना है कि आनुवंशिक सुरक्षा उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखती है। दीर्घायु से जुड़े कई जीन पहचाने जा चुके हैं। अनेक आबादी-आधारित अध्ययनों में फाक्स3 के कुछ बेरिएंट शतायु व्यक्तियों में अधिक पाए गए हैं। लेकिन कहानी केवल जीनों की नहीं है। ब्राजील की इन बहनों का जीवन बताता है कि पर्यावरण और जीवनशैली भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ताजा भोजन और प्राकृतिक परिवेश में रहना उनके जीवन का हिस्सा था। यह सब स्वास्थ्य पर दैनिकीयक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। एक ही परिवार में कई लोगों का शतायु होना मजबूत आनुवंशिक संकेत देता है, फिर भी समुदाय और परिवार का सहयोग भी स्वस्थ वृद्धावस्था में निर्णायक भूमिका निभाता है।
बहरहाल, हम यह कह सकते हैं कि लंबी उम्र का राज 'जीन ब्राना जीवनशैली' का सरल ढंढ नहीं, बल्कि दोनों के बीच जटिल संवाद का परिणाम है। निकट भविष्य में इस संवाद की भाषा को समझने में सफलता मिल सकती है। (लेखक विज्ञान संचारक हैं)

योग्यता को मिले प्राथमिकता

'कसी जाए मंत्रियों के चयन की कसौटी' शीर्षक से प्रकाशित राजीव सचान के आलेख में भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे पक्ष को रेखांकित किया गया है, जिस पर गंभीर चर्चा आवश्यक है। वास्तव में लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि योग्य, दूरदर्शी और परिणाम देने वाली टीम के गठन में निहित होती है। ऐसे में, मंत्रिमंडल गठन केवल राजनीतिक संतुलन का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विषय है। दुर्भाग्य से दशकों तक मंत्रियों को अनेक बार जातीय समाकण, क्षेत्रीय दबाव, गठबंधन की विश्वासा अथवा राजनीतिक पुरस्कार के स्वयं में देखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई महत्वपूर्ण मंत्रालय ऐसे व्यक्तियों के हाथों में पहुंचे, जिनकी न तो विषयगत समझ पर्याप्त थी और न ही प्रशासनिक दृष्टि। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व आवश्यक है, किंतु प्रतिनिधित्व कभी भी योग्यता का विकल्प नहीं बन सकता। विविधता और दक्षता का संतुलन ही स्वस्थ शासन की पहचान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मंत्रियों के चयन के लिए, कुछ स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित किए जाएं। केवल राजनीतिक बरिष्ठता या चुनावी उपयोगिता किसी मंत्रालय का आधार नहीं हो सकती। जिस प्रकार निजी क्षेत्र में प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन होता है, उसी प्रकार मंत्रियों के हाथों का भी समय-समय पर सार्वजनिक मूल्यांकन करना चाहिए। यदि मंत्रिमंडल में योग्यता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी, तो प्रशासनिक व्यवस्था स्वतः अधिक उत्तरदायी, परिणामोन्मुख और जनविश्वस के योग्य बनेगी।
विमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

मेलबाक्स

आम जन से सरकार का जुड़ाव
बुधवार को प्रकाशित आलेख 'मोदी की समावेशी राजनीति' में लेखक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सफल राजनीति का वर्णन किया है। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का एक प्रमुख आधार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र रहा है। उन्होंने अपनी राजनीति में जाति, वर्ग और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। आज भाजपा का जनाधार समाज के सभी वर्गों तक विस्तारित हुआ है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं जनधन, उज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, हर घर जल और किसान सम्मान निधि का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। सरकार का कार्यकालाप वसुधैव कुटुम्बकम् की संस्कृति पर आधारित है।
हिमांशु शेखर केसपा, गयाजी, बिहार

अवसरवादी दृष्टिकोण
'व्यर्थ का विरोधपत्र' शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख भारतीय राजनीति के उस गहरे विरोधाभास को रेखांकित करता है जहाँ संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता अब राष्ट्रीय सहमति के बजाय चुनावी हार-जीत की सहूलियत से तय होने लगी है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के विरुद्ध 23 विपक्षी दलों द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश

को पत्र लिखना पहली नजर में लोकतांत्रिक सजगता प्रतीत हो सकता है, परंतु इसकी इनसाइड स्टोरी एक गंभीर प्रशासनिक संशय और राजनीतिक नैराश्य को परिलक्षित करती है। लोकतंत्र का बुनियादी स्तंभ एक नृतिहित और पारदर्शी मतदाता सूची है। यदि मृत, फर्जी या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने की तकनीकी और जमीनी प्रक्रिया को भी वोट चोरी के राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ दिया जाएगा, तो व्यवस्था का मूल ढांचा ही ढह जाएगा। असम, बिहार और बंगाल के चुनाव परिणाम प्रमाण हैं कि जब परिणाम अनुकूल हों तो संस्थाएं निष्पक्ष हो जाती हैं, अन्यथा वे पक्षपाती नजर आती हैं। यह अवसरवादी दृष्टिकोण जनमानस में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करता है। विपक्ष का यह तर्क आंशिक रूप से वैध हो सकता है कि केवल साफ्टवेयर और प्लॉगिंरटम के भरोसे नागरिकों के अधिकार नहीं छीने जा सकते। किंतु समाधान संगठनात्मक क्षमता मजबूत करने में है।
प्रमोद कुमार गोयल, मेरठ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा ई-मेल: response@jagran.com



डॉ. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

आजकल

तीव्र प्रगति की राह में बाधाओं की पहचान

भारत में चीन के स्तर की औद्योगिक प्रगति की आकांक्षा की जाती है। लेकिन भारत की संस्थाएं और व्यवस्थाएं परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के बजाय, अलग-अलग पक्षों के हितों और आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए बनाई गई हैं। जैसे-जैसे कारखानों, बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और स्मार्ट सिटी के निर्माण में देरी बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे हमारी शासन-व्यवस्था ही विकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही है। प्रशासनिक क्षमता में व्याप्त कमियों को दूर करते हुए देश की प्रगति की गति को बढ़ाया जा सकता है

शहरों को परिवहन, आवास, सफाई-सफाई और कुशल प्रशासन चाहिए होता है। औद्योगिक कारिडोर के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न मंत्रालय, नियामक, राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन लंबे समय तक एक ही दिशा में मिलकर काम करें। जब विकास के ये खरे हिस्से एक साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाते, तो प्रगति की गति धीमी हो जाती है।

भारत के पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है। कमी अगर किसी चीज की है, तो वह है समय पर जमीन हासिल करने, मंजूरीयों दिलाने, बुनियादी ढांचे को जोड़ने और प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करने की क्षमता को। विकास सिर्फ कागजी नीतियों से नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक कुशलता से होता है। यह अंतर इसलिए मायने रखता है क्योंकि आर्थिक विकास अब सिर्फ भारी निवेश पर नहीं, बल्कि विभागों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है।

चीन के विकास की कहानी : अक्सर चीन की कामयाबी का श्रेय वहां की तानाशाही या कम्युनिस्ट व्यवस्था को दिया जाता है। यह स्पष्टीकरण राजनीतिक रूप से तो सुविधानजनक हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से अधूरा है। चीन की असली ताकत उसकी प्रशासनिक क्षमता थी। साल 2008 से 2023 के बीच चीन ने 45 हजार किलोमीटर से अधिक की हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का निर्माण किया। 1980 में जहां उसकी शहरीकरण की दर लगभग 20 प्रतिशत थी, वह आज बढ़कर 65 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। बंदरगाहों, निर्यात क्षेत्रों और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के आस-पास पूरे के पूरे औद्योगिक इकोसिस्टम खड़े कर दिए गए। चीन की उपलब्धि सिर्फ

यह नहीं थी कि उसने कारखाने बनाए, बल्कि उसने ऐसी संस्थाएं बनाई जो उन कारखानों को हर संभव मदद दे सकें।

चीन ने जमीन अधिग्रहण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंटरनेट/टेलीकॉम प्लानिंग को कभी भी मंजूरीयों की सरकारी फाइलों में सालों-साल भटकने नहीं दिया गया। फैसेल लिए गए और प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। गलतियां भी हुईं, कई बार बहुत बड़े पैमाने पर हुईं, लेकिन काम कभी ठप नहीं हुआ। भारत की चुनौती इसके ठीक उल्टे हैं। यहां शक्तियां मंत्रालयों, राज्यों, रेगुलेटरी, अदालतों, नगर निकायों और स्थानीय समुदायों के बीच बंटी हुई हैं। हर संस्था अपनी जगह सही भूमिका निभाती है, लेकिन इन सबसे मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था बनती है जहां किसी योजना को लागू करना अंतहीन समझौतों का खेल बन जाता है। यह अंतर आर्थिक रूप से बहुत भारी पड़ता है।

देरी होने से कंपनियों की वित्तीय लागत बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाने से पहले लंबे समय तक अपनी पूंजी फंसाकर रखनी पड़ती है। नियमों को स्पष्ट न होना निवेश के फैसलों को और मुश्किल बना देता है। जो समस्या प्रशासनिक उलझन से शुरू होती है, वह अंत में देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए खतरा बन जाती है। भूमि अधिग्रहण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सभी को जमीन की जरूरत होती है। पर जमीन हासिल करने में लंबी बातचीत, अदालतों मुकदमेबाजी और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता है। इनमें से कोई भी प्रक्रिया अनुचित नहीं है- लोकतंत्र का



विकास को संभव बनाने वाले सभी विभाग जब आपस में समन्वय कायम रखते हैं तो प्रगति तीव्र गति से होती है। डाइल

प्रशासनिक दक्षता के साथ धरातल पर कार्य में तेजी

उद्योगीकरण हमेशा अपने साथ कुछ विजेता और कुछ पराजित लेकर आता है। जमीन अधिग्रहित करनी पड़ती है, इन्फ्रास्ट्रक्चर कारिडोर से स्थानीय प्रभावित होनी हैं, और पर्यावरण से जुड़े समझौते करने ही पड़ते हैं। दुनिया की हर सफल औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने इन तनावों का सामना किया है। सरकारों ने कड़े फैसले लिए और उनके राजनीतिक परिणामों को भुगता। भारत अक्सर कुछ अलग करने की कोशिश करता है। वह उद्योगीकरण के फायदे तो चाहता है, लेकिन उससे पैदा होने वाले टकरावों से बचना चाहता है। परिणामस्वरूप, प्रोजेक्ट्स अंतहीन विचार-विमर्श, मुकदमों या समझौतों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कड़े फैसलों को सुलझाने के बजाय उन्हें आगे के लिए टाल दिया जाता है।

यहां समझौता होगा कि हर विवाद को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता, कुछ मामलों में कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक साहस का मिलान होता है। प्रशासनिक कुशलता की जितनी जरूरी है, राजनीतिक

इच्छाशक्ति भी उतनी ही मायने रखती है। सरकारों को कभी-कभी 'काम की रफ्तार' और 'आम सहमति' के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। भारत आज पहली दुनिया जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर, चीन के स्तर की मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक स्तर की लाजिस्टिक्स तो चाहता है, लेकिन वह उन राजनीतिक कामलों को चुकाने के लिए तैयार नहीं है जो इन बदलावों के साथ आती हैं। इस संतुलन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। फैसलों को तालन खुद में एक राजनीतिक रणनीति बन जाता है, क्योंकि कड़े फैसले लेने से बेहतर उन्हें तालन आसान होता है। लेकिन इस प्रकार के देरी को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

वस्तुतः मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था वाले देशों में सरकारें निवेशकों के लिए अनिश्चितताओं को कम करके प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके विपरीत, भारत में सरकारें उस अनिश्चितता को भरपाई (मुआवजा) देकर कंपनियों को लेने ही पड़ते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक साहस का मिलान होता है। प्रशासनिक कुशलता की जितनी जरूरी है, राजनीतिक

जल्दी मिलेगी? इन्फ्रास्ट्रक्चर कितना भरोसेमंद है? मंजूरीयों कितनी पारदर्शी हैं? और कानूनी विवादों को सुलझाने में कितना वक्त लगेगा? पीएलआइ योजनाओं को अक्सर औद्योगिक नीति के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन वे एक और काम करती हैं। ये सब्सिडियाँ असल में उस तरह की देरी, तालमेल को कमियाँ और प्रशासनिक जोखिमों की भरपाई करती हैं जिन्हें एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। इसलिए हमारी औद्योगिक नीति एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रही है : यह निवेश को भी आकर्षित कर रही है और देश की प्रशासनिक क्षमता को कमी को भी ढक रही है। कारखानों को आकर्षित करने के लिए तो यह तरीका कारगर हो सकता है, लेकिन पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम खड़ा करना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। कारखानों को सब्सिडी का लालच दिया जा सकता है, लेकिन सप्लायर नेटवर्क, प्रशासनिक दक्षता और संस्थगत भरपाई रातों-रात नहीं, बल्कि धीरे-धीरे करना पड़ता है। (डा. विकास सिंह)

काम ही अलग-अलग पक्षों के हितों में संतुलन बनाना है। दिक्कत यह है कि आर्थिक बदलाव आपसी तालमेल पर निर्भर करता है, और यही तालमेल भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ियों में से एक है।

नतीजतन, हमारा विकास माडल रूकावटों और टकरावों से भरा हुआ है। प्रोजेक्ट्स आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन उम्मीद से बहुत धीमी रफ्तार से। निवेशक रुचि तो दिखाते हैं, लेकिन अनिश्चितता के जोखिम की भरपाई के

लिए अधिक लाभ की मांग करते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनता तो है, लेकिन उस गति से नहीं जो औद्योगिक क्रांति को रफ्तार दे सके। विकास तो हो रहा है, लेकिन उस पर 'देरी' का एक गुप्त टैक्स लगा हुआ है।

पोस्ट

श्रीराम करोड़ों देवालियों की आस्था है। इसलिए राम मंदिर से जुड़े हर रुपये का हिसाब भी पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। मंदिर हो या सरकार, जहां जनता की आस्था और धन जुड़ा हो, वहां पारदर्शिता और जनबाधे की अनिवार्य होनी चाहिए। भगवान श्रीराम के नाम से जुड़े हर व्यवस्था को सत्य, मर्यादा और न्याय के मूल्यों पर खरा उतरना चाहिए।

डॉ. मुनीष रायजावड़ @MunishRaizada1

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। एएसआइटी रिपोर्ट के बाद चोरी पर केस भी हो चुका है। सजा उदाहरण बननी चाहिए, लेकिन इसके बहाने पूरे मंदिर को मिले समर्पण पर सवाल उठाना उचित नहीं है। यदि इतनी ही लूट होती तो शायद इतने कम समय में इतना भव्य राम मंदिर तैयार न होता।

नवनीत मिश्रा @navneetmishra99

उत्तर प्रदेश में पिलपकाट के एक हजारों केन्द्र का खुलना यही दर्शाता है कि योगी आदिन्यायन के नेतृत्व में यूपी एक्सप्रेसवे, लाजिस्टिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश में लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि यूपी में रिटेल नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका है।

सुशांत झा @jhasushant

धनंजय प्रताप सिंह



छिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

योग्यता, लंबे अनुभव और पात्रता के बावजूद सरकारी कर्मचारी पदोन्नति का इंतजार करते-करते सेवानिवृत्त हो जाए, तो इसे अन्याय कहेंगे या बिना अपराध की सजा? अधूरे समयों और उम्मीदों की ऐसी कई कहानियाँ मध्य प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी का सच हैं, जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण को लेकर रुकावट के चलते बिना पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त होना पड़ा। फिलहाल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, कर्मचारी संगठनों से लेकर सरकार तक भटक रहे इस मुद्दे को आज भी ठोस निर्णय यानी समाधान सामान्य का इंतजार है।

मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की थी, लेकिन अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस नियम को ही न सिर्फ निरस्त किया,

मध्य प्रदेश डायरी

बल्कि निर्देश भी दिए कि आरक्षण नियमों का लाभ लेकर जिन्हें पदोन्नति मिली है, उसे निरस्त करते हुए उन्हें पदानुवर्त किया जाए। सरकार से लेकर कर्मचारी संगठनों में जबरदस्त हलचल फैल गई और सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। अदालत से यथास्थिति का निर्देश हुआ, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि इस बीच महाशष्ट में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा आने पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मध्य प्रदेश के मामले में समाहित कर लिया। उम्मीद जगाने की विभिन्न राज्यों में कोई ऐसा समाधान निकल आया, जो देश भर में कर्मचारियों के लिए राहत भरा होगा, लेकिन इंतजार अंतहीन होता गया।

दरअसल, इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने भी गंभीरता दिखाते के बजाय वोट बैंक का पूरा ध्यान रखा। कर्मचारी हितों पर जातिगत समीकरण हमेशा भारी पड़ता गया। चुनित को खुश करने में सामान्य वार्ता जुटाया हुआ, वहीं एएससी-एसटी को मौका मिलने पर

व्यवधान ने बढ़ाई पदोन्नति की प्रतीक्षा



बड़ा सवाल है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार की चौष्टक पर पहुंच कर भी ऐसे नियम तय नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को समय रहते पदोन्नति का लाभ मिल जाए। सामान्य वर्ग को पीड़ा है कि राजनीति में हाशिए पर होने के बाद सरकारी सेवाओं में भी यह उपेक्षा का शिकार हो रहा है। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो जब नौकर प्राप्त करने में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, तो पदोन्नति के लिए भी आरक्षण का लाभ

मिलना योग्यता और अनुभव के परिप्रेक्ष्य में कैसे बतौर नियम स्थापित हो सकता है? सबसे बड़ी मुश्किल यह भी है कि देश के सभी राज्यों में पदोन्नति और आरक्षण को लेकर एकसूत्र नियम नहीं बनाए जा सके हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थितियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के नियम पूर्व की स्थिति में लागू हैं। तय समय के बाद पदोन्नति दी जा रही है।

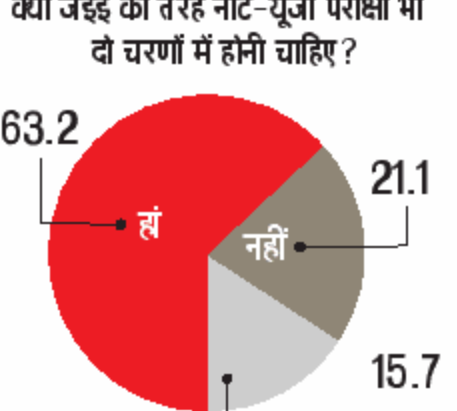
भियान पदोन्नति पाए सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी इन स्थितियों की तुलना अंग्रेजी शासन काल से करने में नहीं चुकते। वे कहते हैं कि उस दौर में अंग्रेज अधिकारियों के लिए कोई नियम-कानून तय नहीं बनते थे, जबकि भारत के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अभाव में भी पदोन्नति में आरक्षण से रोक दिया जाता था। उनकी पीड़ा है कि योग्यता और अनुभव होने के

बावजूद वे अपने अधिकार से वंचित रह गए। ऐसी मुश्किलें वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के साथ भी हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेकर वर्षों से हो रहे अन्याय को रोकने में सफल होगी।

पदोन्नति में आरक्षण कर्मचारियों और सरकार का मुद्दा है, लेकिन इसका खासा भाला सरकारी कामकाज और जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ रहा है। पदोन्नति न होने से महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं या अतिरिक्त प्रभार के बोझ तले दबे हैं, वहीं बड़ी संख्या में समय में पदोन्नति नहीं हो पा रही है।

सुरासन के संकल्प में यह बड़ी बाधा है। कोई संदेह नहीं है कि मोहन सरकार एक नई लकीर खींचना चाहती है, लेकिन अधिकारियों-कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था के बिना यह मुश्किल भरा होगा। ऐसे में सरकार को कर्मचारी हितों के अलावा जनहित और सुरासन के लिहाज से भी पदोन्नति में आरक्षण के मामले में समाधान के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा।

जागरण जन्मत कल का परिणाम



जन्मत का सवाल

क्या सवालो से घिरे राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों के खिलाफ भी एक आइआर होनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

आशा लेकर 'अमन' की पत्र लिखें कुछ लोग, दोस्त बनाना पाक को बहुत बड़ा है रोग। बहुत बड़ा है रोग प्रेम में क्यों ना आए, सी-सी घोड़े खाया प्रेम का गीत सुझाए। जब-जब की है बात मिली है हमें निराशा, धूर्त देश के साथ रहें हम कैसे आशा!

-अमि प्रकाश तिवारी

हिमाचल प्रदेश डायरी



नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हाल में हिमाचल प्रदेश ने दो ऐसे घटनाक्रम देखे जिन्हें सामान्य भाषा और समझ में दो 'छोटो-छोटो' खबरें कहा जा सकता है। एक यह कि हिमाचल प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खात्री इस पद पर अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकारी आवास छोड़कर निजी आवास में चले गए। दूसरी खबर यह कि जनजातीय जिले लाहुल-स्पीति के तिगरत बंध पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पलजोम बुट्टी ने उरफने हुए नाले को बूलाडोजर पर बैठ कर इसलिए पार किया, क्योंकि वह राष्ट्रीय सधन पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का भाग हैं और उनके तिगरत बंध पर न पहुंचने का एक ही अर्थ होता कि वह अपनी ड्यूटी से

मानिए आप, यही लोग आदर्श हैं!

चूक गई। ये दो उदाहरण सरकारी सेवा के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से हैं। सवाल उठता है कि ये दोनों घटनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं।

जिस प्रदेश में कई अधिकारी अपने अधिकार की भावना यानी सेंस आफ पॉइंटिलिटी के सार्वजनिक प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार पा चुके हों, जहां कतिपय कर्मचारी शिकायतों और कराहों के स्रोत बनते हों, वहां ये उदाहरण नहीं सहजे गए तो दुस्साहस ही प्रचार पाएगा, साहस नहीं। कोई कारण है कि सरकार के साथ किसी ने सु उपसर्ग नहीं देखा। क्या बड़ी बात है कि अनिल खात्री ने सरकारी मकान खाली कर दिया? इसलिए बड़ी बात है, क्योंकि आत्मसम्मान, व्यवस्था, व्यक्तिसौजन्य और कार्यसंस्कृति इसी से झलकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े एक अधिकारी पर पुलिस के शीर्ष प्रशासन को पीने दो लाख रुपये से अधिक की पेनल्टी लगाने पड़ी है। क्योंकि जिस पद से वह फरवरी के आरंभ में मुक्त हुए वहां मार्च तक ही ठहर सकते थे। संभव है उनकी भी विवशता रही, कोई कारण रहा हो कि वह आवास नहीं छोड़

रहे, किंतु बाहर तो तथ्य यही है कि आवास नहीं छोड़ा। जो उनके स्थान पर आए हैं, वह अपने पद से जुड़े आवास में न ठहर कर वहाँ और ठहर रहे हैं।

जिस अर्थ में टकरावट पहले भी होती होगी, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता था। परस्पर सम्मान इतना था कि 1997 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मनीषा श्रीधर कांगड़ा से शिमला की उपायुक्त बन कर गईं तो सीधे उपायुक्त आवास में गईं। वहाँ तत्कालीन उपायुक्त शिमला वीसी पारकर ने पहले ही अपना सामान एक कमरे में समेटे रखा था। कहीं कोई टकरावट, 'आवास विस्तार' या अत्यासम्मान नहीं। तरुण श्रीधर बिलासपुर के उपायुक्त बने। उपायुक्त आवास न जाकर विश्राम गृह में ठहरने के लिए पहुंचे ही थे कि लीडलाइन पर बिलासपुर के निवर्तमान उपायुक्त सरोज कुमार दश और उनकी पत्नी का फोन आया कि आप अपने आवास में आएँ। तरुण कहते हैं, 'मैंने कहा कि आप को क्यों तंग करूंगा तो जवाब आया कि इतना बड़ा घर है, मिल कर रह लेते हैं। और उसके बाद दश साहब शिमला चले

गए। श्रीमती दश एवं उनके पुत्र-पुत्री एक माह तक वहाँ रहे। हमलोग परिवार की तरह एक साथ रहे।' इसके बरक्स हाल में हिमाचल में ऐसा मामला भी देखा गया कि आवास को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर हो गई।

आवास के प्रसंग में ही यह सेंस आफ पॉइंटिलिटी नहीं तो क्या है कि हर सरकार बदलने के साथ अधिकारी जिस आवास में जाता है, वहाँ नए सिरे से रंग रोगन या पद ही नहीं बदलवाता, जैसे आवास का पुनः 'उद्धार' भी करता है... उससे उससे पहले वहाँ रहने वाला अधिकारी किसी सुविधाविहीन सादा कुटिया में रह रहा था। यह काम राजनीतिक लोग भी करते हैं, किंतु अधिकारियों की सेंस आफ पॉइंटिलिटी के तेवर ही अलग होते हैं। पॉइंटिलिटी का यह संक्रमण राजनीतिक लोगों या अधिकारियों तक सीमित नहीं है। जिन्हें इन सब पर दृष्टि रखनी है, वे लोग भी लाभार्थी बनते हैं। राजधानी में आवास के तलबगार और भी हैं जिन्हें घर हैं तंग करूंगा तो जवाब आया कि इतना बड़ा घर है, मिल कर रह लेते हैं। और उसके बाद दश साहब शिमला चले



कर्मचारी के पथ पर: बुलाडोजर पर बैठ कर नाला पार करती पलजोम बुट्टी। वीडियो ग्रेव

सेब यदि राजस्थान के अधिकारियों तक गए तो कोई कारण होगा। होली की पार्टी का बिल आयोजक के बजाय सरकार के माथे मढ़ा जा रहा था तो कोई बजह रही होगी।

इस सबमें आदर्श की स्थापना का आग्रह करता है कि अनिल खात्री के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता पलजोम बुट्टी को भी मानक माना जाए। पलजोम कह सकते थे कि परिस्थितियाँ आदर्श नहीं, मौसम ठीक नहीं आदि आदि... किंतु इन सब पर दृष्टि रखनी है, वे लोग भी लाभार्थी बनते हैं। राजधानी में आवास के तलबगार और भी हैं जिन्हें घर हैं तंग करूंगा तो जवाब आया कि इतना बड़ा घर है, मिल कर रह लेते हैं। और उसके बाद दश साहब शिमला चले

वे लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। पलजोम अकेली नहीं हैं। इससे पहले मंडी को कमला देवी को भी उफनती नदी पार करने के लिए सीएम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के संस्थापक सायरस पूनावाला ने दिसंबर, 2025 में घर बुला कर पंच लाख रुपये की सम्मानराशि दी थी। कमला से पहले मंडी के सराज की आशा बर्कर गौता देवी को दुर्गम क्षेत्रों में अपने मोटरसाइकिल के सहारे खसरा और रुबला टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सम्मानित किया था, अपने कैलेंडर के मुखपृष्ठ पर स्थान दिया था। कुल्लू की निर्मला को कैसे भूल सकते हैं आप जो वैक्सोन देने के लिए मल्लाणा जैसे क्षेत्र में 15 किमी बर्फ पर चलायीं

बिजनेस

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|----------------|------------|------------------|------------|------|----------|------------|----------|
| संसेक्स | 76,922.64 | निफ्टी | 24,005.85 | सोना | ₹ 1,44,500 | चांदी | ₹ 2,35,000 | डालर | ₹ 95.16 | कूड | \$ 72.17 |
| | ▲ 443.97 | | ▲ 140.10 | प्रति दस ग्राम | ▼ ₹ 1,300 | प्रति किलो ग्राम | ▲ ₹ 5,000 | | ▲ ₹ 0.60 | प्रति बैरल | |



शेयर बाजार में गिरावट थमी, संसेक्स 444 अंक चढ़ा

मुंबई, प्रेद: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बीच लगातार ठे सत्र की गिरावट के बाद धरेलु शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी दर्ज की गई। बीएसई संसेक्स 443.97 अंक की बढ़त के साथ 76,922.64 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 631.41 अंक चढ़कर 77,110.08 अंक तक पहुंच गया था। एनएसई निफ्टी 140.10 अंक की बढ़त के साथ 24,005.85 पर बंद हुआ। बीएसई संसेक्स मंगलवार को 249.70 अंक और एनएसई निफ्टी 80.50 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। ब्रेट कूड का भाव 1.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72.17 डालर प्रति बैरल के आसपास रहा। संसेक्स में शामिल कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेट्रोल, हिंदुस्तान यूनिटीवर, अटाणी पोर्टर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्टेट बैंक आफ इंडिया प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में शामिल हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाटा स्टील और इन्फोसिस गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225 और चीन का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स बढ़ते में जबकि दक्षिण कोरिया का कसपी गिरावट में रहा। हांगकॉंग के बाजार बंद थे।

76,922.64
पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक

140 अंक
बढ़कर 24,005 पर बंद हुआ एनएसई निफ्टी

2,276
शेयरों में बढ़त दर्ज की गई



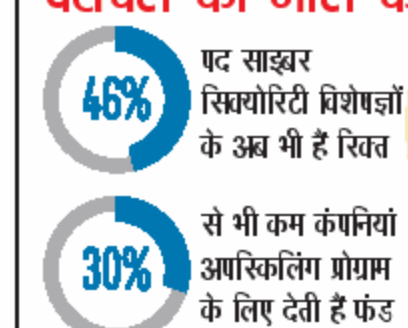
बाजारों ने वर्ष 2026 की दूसरी छमाही की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की है। कूड की नरम कीमतों ने धारणा को मजबूत किया। **विनोद नामर, रिखर्व हेड,** निवोविजिट इन्वेस्टमेंट्स

प्रतिभूति धोखाधड़ी में सेबी ने 221 इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली, प्रेद: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 'पंप-एंड-डंप' आपरेेशन' यानी प्रतिभूति धोखाधड़ी मामले में 221 इकाइयों पर सात साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही व्यक्तिगत निवेशक हनीफ शेख पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 'पंप-एंड-डंप' आपरेेशन' प्रतिभूति धोखाधड़ी को एक रूप है। धोखाधड़ी करने वाले पहले किसी छोटो या कम कारोबार वाली कंपनी के शेयर खरीदते हैं और फिर इंटरनेट मोडिया के जरिये झूठी अफवाह फैलाकर शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाते (पंप) हैं और फिर शेयरों को उच्च कीमतों पर बेच देते (डंप) हैं। यह मामला 2017 से 2020 के बीच पांच शेयरों में बड़े पैमाने पर 'पंप-एंड-डंप' से जुड़ा है। शेख इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। सेबी ने आदेश में कहा कि हनीफ शेख ने एक सुनियोजित धोखाधड़ी साजिश रची, जिसमें 200 से अधिक आपस में जुड़े हुए संस्थान शामिल थे। इन्हें 'पीबी इन्फ्लुएंसर्स', 'कोलेबोरेटर्स' और 'आफलोउअर्स' जैसी भूमिकाएं दी गई थीं, ताकि अवैध लाभ को विभिन्न माध्यमों से गुमाकर शेख या उसके नियंत्रण वाली कंपनियों तक पहुंचाया जा सके। इस घोटाले से करीब 143.79 करोड़ रुपये का अवैध लाभ अर्जित किया गया।

शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर बेचने के मामले में हैं दोषी, व्यक्तिगत निवेशक हनीफ शेख पर 10 करोड़ का जुर्माना

साइबर सुरक्षा क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग कमी



एट साइबर रिपोर्टों में विशेषज्ञों के अब भी है रिक्त। से भी कम कंपनियों अपरिष्कृत प्रोग्राम के लिए देती है फंड।



तकनीकी विशेषज्ञता के साथ कारोबारी समझ रखने वाले साइबर सुरक्षा पेशेवरों की वैश्विक स्तर पर भारी कमी है। जिसके कारण इस क्षेत्र के 46 प्रतिशत एट अब भी रिक्त हैं। सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श कंपनी एक्सवैर की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। 'सेक्योरिटींग द साइबर वर्कफोर्स' नाम की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में 59 प्रतिशत पदों के लिए तकनीकी दक्षता, कारोबार की समझ और नेतृत्व संबंधी कौशल की जरूरत होती है। वहीं मौजूदा कार्यबल में केवल 40 प्रतिशत लोग ही ऐसे पदों पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, आधुनिक साइबर सुरक्षा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के इस्तेमाल, निर्यातकीय जवाबदेही, परिचालन की मजबूती और ग्राहकों के भरोसे पर आधारित है।

एक नजर में

जून में बिजली खपत में 11.62% की बढ़ोतरी
नई दिल्ली: मानसून के देर से आने के चलते जून में भारत की बिजली की खपत 11.62 प्रतिशत बढ़कर 166.46 अरब यूनिट हो गई। पिछले साल की समान अवधि में कुल बिजली खपत 149.13 अरब यूनिट थी। पिछले महीने पीक डिमांड भी जून 2025 के 242.77 गीगावाट से बढ़कर 264.76 गीगावाट हो गई। दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून, 2026 को केरल पहुंचा था। (प्रेद)

सोने में गिरावट जारी, चांदी 5,000 रुपये मजबूत
नई दिल्ली: वैश्विक बाजार में कमजोरी और डालर के मजबूत होने से सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई और यह 1,300 रुपये घटकर 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मंगलवार को यह 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही और यह 5,000 रुपये बढ़कर 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। (प्रेद)

जून में 1.95 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह

आटोमोबाइल व उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेजी का असर, पिछले साल से 14% बढ़ा कलेक्शन

जागरण न्यूज, नई दिल्ली: जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। आटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेजी से जून का जीएसटी संग्रह 1,94,800 करोड़ रहा जो पिछले साल जून के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। जून के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 37,376 करोड़, एसजीएसटी की 45,116 करोड़ तो आईजीएसटी की 1,12,320 करोड़ की रही।

यूपी के टैक्स कलेक्शन में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून माह में उत्तर पिछले के जीएसटी संग्रह में पिछले साल जून के मुकाबले 19 प्रतिशत, पंजाब में 14 प्रतिशत, दिल्ली में आठ प्रतिशत, बिहार में पांच प्रतिशत, हरियाणा में नौ प्रतिशत, तेलंगाना में 11 प्रतिशत तो गुजरात में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

6.32 लाख करोड़ रकम
नालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल संग्रह

आयात से मिलने वाला जीएसटी राजस्व 34% बढ़ा

पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते आर्थिक गतिविधियों में रुकावटों के बावजूद जीएसटी का मासिक संग्रह दो लाख करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। यह देश की आर्थिक मजबूती को दिखाता है। **-एमएस मणि,** हेलाइट इंडिया के पार्टनर

जून में तेजी का सिलसिला जारी है। आटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेजी से जून का जीएसटी संग्रह 1,94,800 करोड़ रहा जो पिछले साल जून के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। जून के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 37,376 करोड़, एसजीएसटी की 45,116 करोड़ तो आईजीएसटी की 1,12,320 करोड़ की रही।

जून में तेजी का सिलसिला जारी है। आटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेजी से जून का जीएसटी संग्रह 1,94,800 करोड़ रहा जो पिछले साल जून के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। जून के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 37,376 करोड़, एसजीएसटी की 45,116 करोड़ तो आईजीएसटी की 1,12,320 करोड़ की रही।

जून में तेजी का सिलसिला जारी है। आटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेजी से जून का जीएसटी संग्रह 1,94,800 करोड़ रहा जो पिछले साल जून के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। जून के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 37,376 करोड़, एसजीएसटी की 45,116 करोड़ तो आईजीएसटी की 1,12,320 करोड़ की रही।

जून में तेजी का सिलसिला जारी है। आटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेजी से जून का जीएसटी संग्रह 1,94,800 करोड़ रहा जो पिछले साल जून के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। जून के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 37,376 करोड़, एसजीएसटी की 45,116 करोड़ तो आईजीएसटी की 1,12,320 करोड़ की रही।

जून में तेजी का सिलसिला जारी है। आटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेजी से जून का जीएसटी संग्रह 1,94,800 करोड़ रहा जो पिछले साल जून के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। जून के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 37,376 करोड़, एसजीएसटी की 45,116 करोड़ तो आईजीएसटी की 1,12,320 करोड़ की रही।

स्टार्टअप के युवा उद्यमी टिकाऊ कारोबार पर कर रहे फोकस

मुंबई, प्रेद: हरुन इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों द्वारा जुटाई गई आधी से ज्यादा रकम प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बाजार विस्तार में लगाई जा रही है। यह टिकाऊ कारोबार बनाने पर बढ़ते फोकस को दिखाता है। इन कंपनियों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर 27 प्रतिशत और बाजार व भौगोलिक विस्तार में 26 प्रतिशत पूंजी लगाई है। नतीजे बताते हैं कि कंपनियों के युवा संस्थापक गैर-जल्दरूरी खर्चों के बजाय लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट बनाने और मार्केट विस्तार को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे निवेशकों का काफी ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं।



रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतपे ने सबसे ज्यादा 18 राउंड में पूंजी जुटाई है। इसके बाद सिंगल एनर्जी और जेटो का नंबर आता है। इन्होंने 15-15 राउंड में पूंजी जुटाई है। जबकि पिक्सल ने 11 राउंड और बाज बाइक्स ने पूंजी जुटाने के अब तक नौ राउंड पूरे किए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जेटो इस साल की सबसे ज्यादा फंडिंग पाने वाला स्टार्टअप है। उसने अब तक 2.3 अरब डालर जुटाए हैं। इसके बाद फिन्टेक भारतपे का नंबर आता है और उसने 65 करोड़ डालर जुटाए हैं जबकि क्लॉन मोबिलिटी कंपनी सिंगल एनर्जी 9.9 करोड़ डालर जुटाकर तीसरे स्थान पर है। पूंजी जुटाने में स्पेस टेक्नोलॉजी भी पीछे नहीं हैं। 20 साल के एग्लोसिक के ऑकार सिंह बत्रा और सुपरमेमोरी के धन्य शाह इस सूची में सबसे कम उम्र के लोग हैं।

चार साल बाद जून में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की बढ़ोतरी धीमी रही

नई दिल्ली, प्रेद: देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों की वृद्धि जून में धीमी पड़ गई। नए कारोबारी आर्डर और अंतरराष्ट्रीय बिक्री की वृद्धि दर नरम रहने से खरीद, रोजगार और उत्पादन की रफ्तार भी कम रही। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया बिनिर्माल क्लय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई के 55.0 से घटकर जून में 54.2 पर आ गया। यह 2022 के मध्य के बाद से क्षेत्र की स्थिति में दूसरा सबसे कमजोर सुधार दर्शाता है।

पीएमआई में 50 से ऊपर का स्तर गतिविधियों में विस्तार और 50 से नीचे का स्तर संकुचन को दर्शाता है। सर्वेक्षण के अनुसार, कई कंपनियों ने मांग की स्थिति में सुधार की बात कही, जबकि कुछ कंपनियों ने अपने उत्पादों की मांग कमजोर रहने और बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया। भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय मांग जून में भी

बढ़ी, लेकिन इसकी रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही। इसकी वजह कुछ यूरोपीय बाजारों में कमजोर बिक्री बताई गई। कीमतों के मोर्चे पर, मांग की वृद्धि कमजोर पड़ने से उत्पादक कीमतें बढ़ाने के प्रति कम उत्सुक दिखे। उत्पादन कीमतों में बढ़ोतरी मध्यम रही और पिछले तीन महीनों में सबसे कम दर्ज की गई। इस बीच, मांग और बाजार की स्थिति को लेकर चिंता के कारण जून में निवेशकों और कारोबारियों का भरोसा कमजोर

बढ़ी, लेकिन इसकी रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही। इसकी वजह कुछ यूरोपीय बाजारों में कमजोर बिक्री बताई गई। कीमतों के मोर्चे पर, मांग की वृद्धि कमजोर पड़ने से उत्पादक कीमतें बढ़ाने के प्रति कम उत्सुक दिखे। उत्पादन कीमतों में बढ़ोतरी मध्यम रही और पिछले तीन महीनों में सबसे कम दर्ज की गई। इस बीच, मांग और बाजार की स्थिति को लेकर चिंता के कारण जून में निवेशकों और कारोबारियों का भरोसा कमजोर

बढ़ी, लेकिन इसकी रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही। इसकी वजह कुछ यूरोपीय बाजारों में कमजोर बिक्री बताई गई। कीमतों के मोर्चे पर, मांग की वृद्धि कमजोर पड़ने से उत्पादक कीमतें बढ़ाने के प्रति कम उत्सुक दिखे। उत्पादन कीमतों में बढ़ोतरी मध्यम रही और पिछले तीन महीनों में सबसे कम दर्ज की गई। इस बीच, मांग और बाजार की स्थिति को लेकर चिंता के कारण जून में निवेशकों और कारोबारियों का भरोसा कमजोर

बढ़ी, लेकिन इसकी रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही। इसकी वजह कुछ यूरोपीय बाजारों में कमजोर बिक्री बताई गई। कीमतों के मोर्चे पर, मांग की वृद्धि कमजोर पड़ने से उत्पादक कीमतें बढ़ाने के प्रति कम उत्सुक दिखे। उत्पादन कीमतों में बढ़ोतरी मध्यम रही और पिछले तीन महीनों में सबसे कम दर्ज की गई। इस बीच, मांग और बाजार की स्थिति को लेकर चिंता के कारण जून में निवेशकों और कारोबारियों का भरोसा कमजोर

सहारनपुर में आबावा कुते ने बालक को नोच-नोच कर मार डाला

जास, सहारनपुर: आबावा कुतों के आतंक पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। परन्तुन की दुकान से खाने का सामान लेने गए बालक पर आबावा कुते ने हमला कर दिया। कुलु ही देर में नोच-नोचकर अधमारा कर दिया। अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई। नाराज लोगों ने आबावा कुतों को पकड़वाया की मांग की है।

अमेरिका ने रूस संबंधी प्रतिबंध सूची से चार भारतीय कंपनियों को हटाया

वाशिंगटन, प्रेद: अमेरिका ने रूस से संबंधित अपने प्रतिबंधों की सूची से चार भारतीय कंपनियों के नाम हटा दिए हैं। इन कंपनियों पर रूस के सैन्य-औद्योगिक अड्डे को उन्नत तकनीक और उपकरणों की आपूर्ति करने के आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी वित्त विभाग की विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की विशेष रूप से नामित नागरिक और प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची से इन कंपनियों के नाम हटाए गए हैं। वित्त विभाग की ओर से मंगलवार को साझा की गई जानकारी के अनुसार, जिन चार कंपनियों से प्रतिबंध हटाया गया है, उनमें हैदराबाद स्थित आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, लोकेश मशीन लिमिटेड, अहमदाबाद स्थित गैलेक्सी बेयरिंग्स और नई दिल्ली स्थित

राष्ट्रीय फलक

दिवालिया प्रक्रिया में ईडी कार्रवाई पर रोक की अपेक्षा नहीं कर सकती कंपनी

नई दिल्ली, प्रेद: नेशनल कंपनी ला अपीलाट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कहा है कि दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया से गुजर रही कोई कंपनी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर रोक की अपेक्षा नहीं कर सकती है। कंपनी इसकी आड़ में अपनी संपत्ति को बचाने की कोशिश नहीं कर सकती उसने इसकी अपराध के जरिये अर्जित की हो। इसी के साथ एनसीएलटी ने ईडी की प्रिवेंशन आफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत सिद्धि बिनायक लाजिस्टिक लिमिटेड पर कार्रवाई को सही बताया है और उस पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अपीलाट ट्रिब्यूनल ने कहा, पीएमएचए के तहत ईडी की किसी भी जर्बती की कार्रवाई की न्यायिक प्रक्रिया के तहत समीक्षा होगी।

मास्टरमाइंडों के खिलाफ लुकआउट नोटिस की तैयारी

जास, पटना: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी और परीक्षा रद्द होने के बाद, अब जांच एजेंसियां इस रैकेट की आखिरी कड़ी तक पहुंचने की कोशिश में लगी हैं। इस सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस की एक विशेष टीम बिहार में डेर डाले हुए है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड बिजेन्द्र गुप्ता और कपिल दहिया के देश छोड़ भागने की आशंका है, जिसे देखते हुए पुलिस दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। महाराष्ट्र सरकार के कड़े रुख को संकेत देते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ मकोका के तहत भी सख्त

एफएसएसएआइ ने पेंसिको सहित छह एनर्जी ड्रिंक कंपनियों को थमाए नोटिस

नई दिल्ली, प्रेद: खाद्य नियामक एफएसएसएआइ ने एनर्जी ड्रिंक बेचने वाली रेड बुल और पेंसिको इंडिया समेत छह कंपनियों को नोटिस ब्राइंडिंग और भ्रामक दावों के लिए गिरफ्तार जारी किए हैं। एफएसएसएआइ ने कहा कि उसने एनर्जी ड्रिंक के लिए कोई मानक अधिसूचित नहीं किया है। एफएसएसएआइ ने इंटरग्राम पर एक पोस्ट में कहा- "एफएसएसएआइ ने कई पेय ब्रांडों को नोटिस जारी किए हैं जोकि एनर्जी ड्रिंक होने का दावा करते हैं, उन पर नोटिस ब्राइंडिंग व गुमराह करने का आरोप है। इन छह ब्रांडों में रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पेंसिको पेट्रोलॉलाइन रश एनर्जी ड्रिंक, रिलायंस प्रोडक्ट्स का कैप्सा एनर्जी ड्रिंक- गोल्ड बूस्ट, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, हेल एनर्जी व कोका-कोला का मास्टर एनर्जी ड्रिंक शामिल हैं।

संपादकीय बाई गेल्या...!

बाई आल्या, त्यांनी पहिले पाऊल टाकले आणि अवधी रंगभूमी उजळून गेली. स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिलेलेल्या विजया मेहता रंगभूमीवर आल्या, तो काळच भारावलेला होता. स्वातंत्र्यानंतर नवा देश उभा राहत होता. महाराष्ट्राचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व सिद्ध होत होते. नवनव्या प्रवाहांना आवाज मिळू लागला होता. पालावरची माणसे पुस्तकाच्या पानावर येत होती. डुलकी घेत असलेल्या मराठी साहित्याला भालचंद्र नेमाडे यांच्या 'कोसला'ने जागे केले होते. बाबूराव बागुल, नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे, शंकर पाटील मराठी सारस्वतांना वेगळे विश्व दाखवत होते. विजय तेंडुलकर, जयवंत ढळवी नाटकाची परिभाषा बदलून टाकत होते. याच काळात वैश्विक भान असलेल्या विजयाबाईंनी मराठी रंगभूमीचे व्याकरण बदलून टाकले. मराठी रसिकांना त्यांनी जग दाखवले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय रंगभूमीला दिशा दिली. विजया मेहता या खरे तर अत्यंत कसदार अभिनय करणाऱ्या देखण्या अभिनेत्री; मात्र दिग्दर्शनाकडे त्यांचा नैसर्गिक कल होता. लंडनला जाऊन नाट्यप्रशिक्षण घेऊन आलेल्या त्या मराठी रंगभूमीवरील पहिल्या रंगकर्मी. 'अॅन्सर्ड' नाटकाची ओळख मराठी रंगभूमीला कोणी करून दिली असेल, तर ती विजया मेहतांनी! मराठी रंगभूमीला त्यांनी काय दिले नाही? व्याकरण दिले. गती दिली. शास्त्र दिले. जगाचे भान दिले. सौंदर्यशास्त्र दिले. नाटक तरी किती सांगावीत! 'बॅरिस्टर', 'हमीदाबाईची कोठी', 'पुरुष', 'यशोदा', 'संध्याछाया', 'वाडा चिरेबंदी'. प्रायोगिक रंगभूमीची मूळमेढ तार त्यांनी रोवलीच, पण प्रगल्भ व्यावसायिक नाटकही दिली. मुख्य म्हणजे, बाईंच्या विद्यापीठात अनेक लेखक, कलावंत, दिग्दर्शक घडले. त्यांच्या तालमीत तयार झाले. शेक्सपियरच्या 'ऑथेल्लो' या नाटकाचे मराठी रूपांतर असलेल्या 'झुंजारराव' या नाटकात 'कमळजा' म्हणून त्या दिसल्या! 'नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा'मध्ये इब्राहिम अल्काझी त्यांना भेटले आणि मग एक अनुभवसंपन्न, विचारसमृद्ध असे रंगवंत सुरु झाले. संस्थानिक अधिष्ठानाशिवाय रंगभूमी विस्तारणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर बाईंनी 'रंगायन' ही संस्था सुरू केली. विजय तेंडुलकर, डॉ. श्रीराम लागू, विजया मेहता असे प्रतिभावंत एकत्र आल्यानंतर रंगभूमीवर काय चमत्कार घडतो, तो रसिकांनी तेव्हा अनुभवला. सादरीकरण, अभिनय, दिग्दर्शन यात नवेपणा काय असतो, याचा धडा त्यांनी दिला. अनेक संस्थांसोबत तर त्यांनी काम केलेच; पण स्वतःच त्या एक संस्था झाल्या होत्या. कला ही काही शिकण्याची गोष्ट नाही, असे मानण्याचा तो काळ. कवी, लेखक, कलावंत हे जन्मावेच लागतात, अशी भूमिका सर्वमान्य. जन्मदत्त काही असेलच; मात्र प्रयत्नपूर्वक, परिश्रमपूर्वक, अभ्यास करून, शिस्तबद्ध पद्धतीने अनेक गोष्टी करता येतात, हे रंगभूमीला विजया मेहता यांनी तेव्हा शिकवले. त्यांना पूर्णत्वाचा ध्यास, प्रयोगाची आस होती. अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र अशा विषयांमध्ये मुंबई विद्यापीठातून पदवी मिळवल्यानंतर नाटकाच्या ओढीनूच त्यांनी दिल्ली गाठली. मग त्या जगभर फिरल्या आणि जग त्यांनी इथे आणले. मॅक्सिम गॉर्की, आयनेस्को, ब्रेख्त मराठी माणसापर्यंत पोहोचले. मराठी रंगभूमीवर ब्रेख्तियन शैलीचा आविष्कार घडवला. विजया मेहता यांचे वैशिष्ट्य असे की, त्या स्वतः तर प्रतिभावंत होत्याच; पण सर्वसामान्य माणसांपर्यंत नाटक पोहोचले पाहिजे, अशी त्यांची मनापासून इच्छा होती. त्यासाठी एखाद्या चळवळीप्रमाणे त्या रंगभूमीसाठी काम करत राहिल्या. नव्या मुला-मुलींसाठी कार्यशाळा घेत राहिल्या. 'रावसाहेब', 'पेस्तनजी' अशा चित्रपटांचे दिग्दर्शनही त्यांनी केले. त्यासाठी त्यांना पुरस्कारही मिळाले. मात्र, नाटक हेच त्यांचे पहिले प्रेम होते. भारतीय रंगभूमीसोबतच आंतरराष्ट्रीय रंगभूमीवरही त्यांनी काम केले. जर्मन रंगभूमीवरही विजया मेहता यांनी आपला ठसा उमटवला. गेली काही वर्षे त्या तशा सक्रिय नव्हत्या. मात्र, काही माणसांचे असणारे देखील आश्वासक असे. बाई तशाच होत्या. विजय तेंडुलकर आज आपल्यात नाहीत. डॉ. श्रीराम लागू गेले. विजया मेहता यांच्या जाण्यामुळे एक पर्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. बाईंनी नाटक उभी केली, तो काळ वेगळा होता. आता जग आमूलाग्र बदलले आहे. नवनव्या माध्यमांनी जग व्यापून टाकले आहे. 'कनेक्ट' जगातील माणसाचे दुभंगलेले एकटेपण अधिक गडद होऊ लागले आहे. या दुभंगलेपणाचे दर्शन घडवणारा 'बॅरिस्टर' मात्र आज दिसत नाही. उरतो तो 'आठवणींचा गोष्ट'. आपण काय काय गमावले आहे, याचा अडमस येत राहतो. एकाकी वाटू लागते. आणि अशावेळी बाई आपल्याला सोडून गेल्या आहेत..!

जगभर

३ आज्यांमुळे उलगडलं शंभरीपार जगण्याचं रहस्य

ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथे राहणाऱ्या असाऊन्या झुलिया दि देउस नुनेस यांचे वय १०३ वर्षे आहे. दुसऱ्या आजी जोर्झादे दि देउस मोटा यांचे वय १०४ वर्षे आहे, तर तिसऱ्या लेविटा दि देउस नुनेस यांचे वय तब्बल १०९ वर्षे आहे. या तिन्ही आज्यांनी या वयात जागतिक विक्रम केला आहे!

या तिन्ही महिला ब्राझीलच्या असून, खापरपणज्या आहेत. आजही त्या या वयात अत्यंत निरोगी आयुष्य जगत आहेत. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे या तिन्ही सख्ख्या बहिणी आहेत! जगातील सर्वाधिक वयाच्या तीन बहिणी म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये त्यांची नोंद झाली आहे.

त्यांचे वैशिष्ट्य इथेच संपत नाही. या तिन्ही बहिणींचे एकत्रित वय ३१६ वर्षे आहे. त्यांच्या या दीर्घायुष्यामुळे शंभर वर्षे जगण्याचे रहस्य शोधण्याच्या दिशेने शास्त्रज्ञांना महत्त्वाचे धागेदोरे

मिळाले आहेत. त्यांच्या आयुष्याचा अभ्यास करून आम्ही लवकरच काही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू. शंभरीपार आयुष्य जगण्याचे गुप्तितय उलगडू शकते, असा त्यांचा विश्वास आहे. त्यासाठी ब्राझीलच्या शास्त्रज्ञांनी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे नाव 'डीएनए लॉन्गोवो प्रोजेक्ट' आहे. या प्रकल्पाचे नेतृत्व ब्राझीलमधील साओ पाउलो विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ मयाना जॅन्झ करत आहेत. वृद्धत्वामागील जैविक घटक शोधणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

या तीन बहिणींच्या अभ्यासामुळे काही मोजके लोक इतरपेक्षा अधिक काळ का जगतात आणि वाढत्या वयातही शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त कसे राहतात, हे शास्त्रज्ञ समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वाढत्या वयानुसार शारीरिक व मानसिक क्षमतांमध्ये घट का होते, तसेच आयुष्य



वाढवण्यासाठी जबाबदार असलेले घटक कोणते, याचाही शोध शास्त्रज्ञ घेत आहेत.

दीर्घायुष्य आणि निरोगी आयुष्य जगण्याची इच्छा प्रत्येकालाच असते. त्यामुळे माणसाचे आयुष्य कसे वाढवता येईल, यासाठी जगभर संशोधन सुरू आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हेदेखील स्वतःच आयुष्य वाढवण्याबाबत सातत्याने प्रयत्न करत असतात. आता कदाचित दीर्घायुष्याचे रहस्य खरोखरच उलगडू शकते.

सेतू

'गोशूइन'च्या जेवढ्या आठवणी, तेवढेच जपानी नियमही...

'गोशूइन' म्हणजे तांबडा शिक्का. त्यासाठी ३०० ते ५०० येन लागतात. ते रोख घ्यायचे. सुट्टे मागायचे नाहीत. असे अगणित अलिखित, पण कडक नियम



मयुरेश कुलकर्णी
जपानी भाषा, साहित्य, इतिहासाचा अभ्यासक, अनुवादक

जपानमधल्या प्रेक्षणीय स्थळांना भेट देताना आम्ही नेहमीच नवनवीन सुविनियरसंस्था शोधत असायचो. क्योटोमध्ये फिरताना एक अखंडा शिवाय संपत आला, तरी मॅनेट, घंटा, जपानी पंखे, बाहुल्यव्यतिरिक्त काही सापडेना. संध्याकाळी एका सुरेख मंदिरात गेलो. प्रवेशद्वारापाशीच त्या मंदिराचं ऑफिस होतं. तिथे एकाच आकाराच्या बऱ्याच वड्या लावल्या होत्या. त्या मंदिराची सुवर्णकृती त्या वड्यांवर रेखलेली होती. मंदिराच्या दुसऱ्या कोप्यात तशाच वड्या घेऊन माणसं रंगाबिंबा लावून उभी होती. मला नवल वाटलं. हे काय, कसली रंग म्हणून चौकशी केली, तेव्हा

आम्ही शोधत होते ते नवलाईचं सुविनियर असं 'गोशूइन' रूपाने मिळालं.

सश्रद्ध जपानी लोक पूर्वी धार्मिक ग्रंथ हाताने लिहून काढत आणि ते मंदिरात दान करत. त्याची पावती म्हणून त्यांना मंदिरातून एक शिक्का तारीखवार घालून दिला जात असे. त्यावर मंदिराची रेखाकृती, क्वचित बुद्धप्रतिमा असे. मंदिरातील पुजारी रेखीव अक्षरात तारीख लिहून तो शिक्का पूर्ण करत. कालपरतले मंदिरातून मिळणाऱ्या या शिक्कांचा - 'गोशूइन'चं स्वरूप आधुनिक झालं. आता मंदिरातर्फे मिळणारा शिक्का हवा असेल, तर धर्मग्रंथ लिहून तो दान करण्याची गरज नाही. सर्वसामान्य माणसालाही इच्छा आणि थोडी सवडी असेल तर तो शिक्का मिळतो.

'गोशूइन' म्हणजे तांबडा शिक्का! सगळे शिक्के एकाच ठिकाणी असावेत, यासाठी आता ठराविक



फुजी पर्वतावरील मंदिरात मिळणारं गोशूइन.

आकाराच्या चौरसाकृती बिनेरेगांच्या वड्या मिळतात. मंदिराच्या आवारात दिसलेल्या सुंदर कव्हरच्या वड्या या त्याच होत्या. त्या वड्यांना म्हणतात 'गोशूइनचो'. क्योटोचं 'किंकाकुजी', 'कियोमिझुदेरा', नाराचं 'तोदाइजी' अशा प्रसिद्ध मंदिरांत, फुजी पर्वताच्या शिखरावर असलेल्या 'कोनोहानासाकुयाहिमे' या फुजी देवतेच्या देवळात किंवा कुठल्याही छोट्या देवळांमध्ये दर्शन घेतल्यावरही गोशूइन देतात.

अर्थात गोशूइनच्या प्रत्येक शिक्क्यानिशी जेवढ्या आठवणी आहेत, तेवढेच जपानी नियमही...

'श्रीमंतांचे ठीक, सर्वसामान्य माणसे कुठे जातील?'

समाजातील सर्वात शेवटच्या, दुर्लक्षित माणसाविषयीची बाबूजींची तळमळ, आस्था आणि बांधिलकी प्रेरणादायी होती. त्यातून खूप काही शिकता आले



यशवंत भावे
भारत सरकारचे माजी सचिव

ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, 'लोकमत' समूहाचे संस्थापक संपादक आणि माझे ज्येष्ठ स्नेही जवाहरलालजी दर्डा यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाची सांगता झाली आणि आज त्यांच्या जयंतीदिनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईच्या शेअर बाजार चौकात जवाहरलालजींच्या पुतळ्याचे अनावरण होत आहे.

स्वर्गीय बाबूजींसोबत मी काम केले आणि आमचा दीर्घकालीन स्नेही होता. त्यामुळे त्यांच्याविषयी लिहायला घेतल्यावर नेमके काय काय लिहावे, हे उमजना; कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अक्षरशः असंख्य पैलू होते. आमच्या प्रदीर्घ स्नेहकाळात बाबूजींशी निगडित अनेक आठवणी मनात दाटून आल्या आहेत.

मी समक्ष अनुभवलेली त्यांची प्रशासनातील कार्यक्षमता आणि सार्वजनिक सेवाभाव, हा त्यांचा एक ठळक व्यक्तिविशेष होता. विशेषतः एक सक्षम मंत्री म्हणून त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये जे मूलभूत काम केले, त्याबद्दल लिहायचे ठरवले आहे.

बाबूजींच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या या पैलूचा अनुभव मी अगदी जवळून घेतला आहे. अर्थात, राजकारण,

समाजकारण, उद्योग-व्यवसाय आणि सार्वजनिक सेवा, अशा अनेक क्षेत्रांत त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव होता. या प्रत्येक क्षेत्रात ते तितक्याच सहजतेने वावरत आणि एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात तेवढ्याच सफाईने प्रवेशही करत.

त्यांच्या एका गुणाने मला नेहमीच अत्यंत प्रभावित केले. तो गुण म्हणजे दूरदृष्टी राखून भविष्याचा अचूक अंदाज घेत संस्था उभारण्याची बाबूजींची अजोड क्षमता. विजय आणि राजेंद्र या आपल्या कर्तृत्ववान मुलांच्या (जे नंतर माझे मित्रही झाले) सहकार्याने जवाहरलालजींनी १५ डिसेंबर १९७१ रोजी 'लोकमत' या वृत्तपत्र समूहाची स्थापना केली. अनेक शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थाही उभारल्या. या संस्थांनी समाजाच्या जडणघडणीत अत्यंत मोलाचे योगदान दिले आहे. संस्था उभारण्याची जवाहरलालजींची ही परंपरा विजयबाबू आणि राजेंद्रबाबूंनीही पुढे चालू ठेवली आहे.

यवतमाळ येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आणि त्यात यश मिळवले. याशिवायही इतर अनेक संस्थांची उभारणी त्यांनी केली आहे.

यवतमाळचा जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना बाबूजींच्या कामकाजाचे जवळून निरीक्षण करण्याची संधी मला मिळाली. तळागाळातील प्रश्नांची त्यांना असलेली अचूक जाण आणि त्यावर



ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, 'लोकमत' समूहाचे संस्थापक संपादक जवाहरलाल दर्डा यांची आज जयंती. त्यानिमित्त विशेष लेख...

प्रभावी उपाय शोधण्याचे त्यांचे कौशल्य वादातीत होते, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतला आहे. ते उद्योगमंत्री असताना मीही उद्योग मंत्रालयात काम करत होते, त्यामुळे त्यांच्याशी माझा नियमित संबंध येत असे. त्यांची 'क्विज' ही नेहमीच प्रगतिशील आणि दृगामी असे. महाराष्ट्राच्या नव्या औद्योगिक धोरणाच्या निर्मित प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे सखोल आणि नेमके मार्गदर्शन लाभले होते. बाबूजींनी विधानसभेत मांडलेल्या महाराष्ट्राच्या नव्या औद्योगिक धोरणावर त्यांच्या दूरदृष्टीची छाप ठळकपणे उमटलेली होती.

समाजातील सर्वात शेवटच्या, दुर्लक्षित माणसाविषयीची बाबूजींची तळमळ, आस्था आणि बांधिलकी ही माझ्यासाठी प्रेरणादायी होती. त्यातून खूप काही शिकण्यासारखेही होते. मग, ते महाराष्ट्र

औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) असो किंवा महाराष्ट्र राज्य तित महामंडळ (एमएसएफसी) असो, त्यांनी आम्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेला संदेश अगदी स्पष्ट असे.

विकासाचे लाभ महाराष्ट्राच्या दुर्गम आणि सेवासुविधांपासून वंचित असलेल्या, तुलनेने दुर्लक्षित भागांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असे ते नेहमी म्हणत. तो ध्यासच त्यांनी घेतलेला होता. एमआयडीसीच्या इंडस्ट्रियल शेड्स उभारण्याचे काम असो किंवा एमएसएफसीकडून लघुउद्योजकांना वित्तीय साहाय्य, कर्ज देण्याची योजना, या साऱ्या सुविधा प्राधान्याने नेहमी सर्वात शेवटच्या, सर्वसामान्य माणसाला द्या, असे ते आवर्जून सांगत. 'एखादा श्रीमंत माणूस एखाद्या कामासाठी माझ्यापर्यंत पोहोचू शकतो, श्रीमंतांचे ठीक आहे, पण सर्वसामान्य माणसे कुठे जातील? - ते तुमच्याकडेच येणार. त्यांच्या समस्या आपल्या स्वतःच्या आहेत, अशा भावनेने त्यांच्याकडे पाहा. आपण सारे सार्वजनिक सेवेक आहोत, हे नेहमी लक्षात ठेवा. पण, अगदी छोटा उद्योजकसुद्धा आपल्या नशिवाचा शिल्पकार असतो. त्याला त्याचे ध्येय गाठण्यासाठी मदत करा...' हे त्यांचे नेहमी सांगणे असे.

बाबूजी, विजयबाबू आणि राजेंद्रबाबू या तिघांनीही मला दिलेला जिद्दाला आणि पाठबळ मी कधीच विसरू शकणार नाही. विजयबाबू आणि राजेंद्रबाबू यांच्याशी असलेले माझे संबंध आजही अत्यंत दृढ आहेत. बाबूजी आणि त्यांच्या कुटुंबाबरोबरच्या सुखद आठवणी माझ्यासाठी अत्यंत मोलाच्या आहेत, त्या मी आयुष्यभर जपून ठेवीन.

श्रद्धांजली

मराठी रंगभूमीला आधुनिकतेचे व्याकरण शिकवणाऱ्या बाई

विजयाबाईंनी कलाकारांना केवळ अभिनयच शिकवला नाही, नाटकातल्या नावीन्यपूर्ण अवकाशाला आणि प्रयोगाला कवेत घेण्याची दृष्टीही दिली.



सतीश आळेकर
ज्येष्ठ नाटककार

ज्येष्ठ नाट्य दिग्दर्शिका, अभिनेत्री विजयाबाई मेहता यांच्या जाण्याने स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी आणि भारतीय रंगभूमीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा, देदीप्यमान चेहरा काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. मराठी रंगभूमीवर आदराने 'बाई' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विजयाबाईंनी केवळ नाटक सादर केली नाहीत, तर मराठी रंगभूमीचा एक समृद्ध विचार आणि उत्कृष्ट नाटकाचा वस्तुपाठच आपल्यासमोर निर्माण केला.

मराठी रंगभूमीवर शिस्त आणि या रंगभूमीचे आधुनिक व्याकरण पहिल्यांदा जर कोणी सिद्ध केले असेल, तर ते विजयाबाईंनी. त्यांच्या 'रंगायन' या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी हे व्याकरण खऱ्या अर्थाने रुजवले. विजयाबाईंनी त्या काळातील सर्वच नव्या आणि बंडखोर नाटककारांच्या कलाकृतींना मुख्य प्रवाहात आणले. विजय तेंडुलकर, वसंत कानेटकर यांच्यापासून ते जयवंत ढळवी यांच्यापर्यंतच्या सर्व दिग्गजांच्या नाटकांचे दिग्दर्शन करून त्यांनी मराठी

नाटकाचा अवकाश विस्तारला. विजयाबाईंचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी मराठी रंगभूमीला कधीही प्रादेशिकतेच्या चौकटीत संकुचित राहू दिले नाही. युरोपमध्ये ज्या पद्धतीची रंगभूमी त्या काळात आकाराला येत होती, तिचे दर्शन त्यांनी भारतातल्या, इथे महाराष्ट्रातल्या मराठी प्रेक्षकांना घडवले. 'असंगत नाटक' ही संकल्पना त्यांनी मराठीत आणली. फ्रेंच नाटककार यूजीन आयोनेस्को यांच्या 'द चेअर्स' या नाटकाचा त्यांनी केलेला प्रयोग त्या काळात प्रचंड गाजला. या प्रयोगाच्या माध्यमातून त्यांनी जागतिक नाट्यसंस्कृतीच्या जाणिवा मराठी मातीत अत्यंत ताकदीने पेरल्या.

माझी आणि विजयाबाईंची पहिली ओळख मी कॉलेजमध्ये असताना, साधारणपणे १९६७च्या सुमारास झाली. त्या काळापासून विजयाबाईंची नाटके आम्हाला जवळून पाहता आली. आमच्या पिढीचे हे खूप मोठे भाग्य होते की, आम्हाला विजयाबाईं यांच्या ऐन उमेदीच्या आणि सर्जनशीलतेच्या शिखरावर असताना अनुभवायला मिळाल्या. महेश एलकुंचवार यांच्यासारख्या नवोदित नाटककाराची पहिली एकांकिका त्यांनीच रंगमंचावर आणली.

विजयाबाईंनी प्रायोगिक रंगभूमीवर जेवढ्या



ताकदीने काम केले, तेवढ्याच समर्थपणे व्यावसायिक रंगभूमीदेखील गाजवली. पु. ल. देशपांडे यांच्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) सारख्या बलाढ्य संस्थेच्या संचालकपदाची धुरा अत्यंत यशस्वीपणे सांभाळली आणि मराठी तसेच भारतीय रंगभूमीला फार मोठे योगदान दिले.

त्यांच्या अनेक संस्मरणीय कलाकृतींपैकी कोणते एक नाटक, त्यांनी साकारलेल्यापैकी कोणता एक भूमिका आवडली, अशी निवड करता येणे मलातरी कदापि शक्य नाही. त्यांनी दिग्दर्शित केलेली 'बॅरिस्टर', 'यशोदा' ही नाटके आजही मैलाचा दगड मानली जातात. तेंडुलकरांच्या आणि एलकुंचवारांच्या अनेक एकांकिका बाईंनी ज्या संवेदनशीलतेने दिग्दर्शित केल्या, तो एक स्वतंत्र अभ्यासविषय आहे.

माझी वैयक्तिक आणि अत्यंत जिद्दाल्याची

आठवण म्हणजे, माझे 'महानिर्वाण' हे नाटक पाहायला विजयाबाई स्वतः आल्या होत्या. त्यांना ते नाटक प्रचंड आवडले आणि त्यांनी त्या प्रयोगाला मनापासून दाद दिली होती. नाटक क्षेत्रातील एवढ्या मोठ्या शिखराकडून मिळालेली ती कौतुकाची थाप माझ्यासाठी अत्यंत मोलाची, ऊर्जा देणारी ठरली.

पुण्याशी आणि विशेषतः पुणे विद्यापीठाच्या 'ललित कला केंद्रा'शी विजयाबाईंचे अत्यंत जिद्दाल्याचे नाते होते. मी जेव्हा ललित कला केंद्राचा कार्यभार पाहत होते, तेव्हा विजयाबाईं तिथे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आवर्जून यायच्या. त्यांनी आमच्या केंद्रात दोन ते तीन दिवसांची एक विशेष कार्यशाळा घेतली होती. आज कलाविश्वात नाव कमावलेली अभिनेत्री मुक्ता बर्वे आणि 'टि'या' चित्रपटाचा दिग्दर्शक मंगेश हाडवळे हे त्या कार्यशाळेत विद्यार्थी म्हणून सहभागी झाले होते. विजयाबाईंच्या शिस्तटीत आणि त्यांच्या तालमीच्या मुशीत घडण्याची संधी आमच्या विद्यार्थ्यांना मिळाली, हा ललित कला केंद्रासाठी सुवर्णकाळ होता.

कलाकारांना केवळ अभिनय न शिकवता, त्यांनी नाटकातल्या नावीन्यपूर्ण अवकाशाला आणि प्रयोगाला कवेत घेण्याची दृष्टी दिली. त्यांच्या जाण्याने आज संपूर्ण नाट्यसृष्टी पोरकी झाली आहे. आमच्या संपूर्ण पिढीच्या वतीने आणि ललित कला केंद्राच्या वतीने या थोर रंगकर्मीला भावपूर्ण श्रद्धांजली!

(शब्दांकन : नम्रता फडणीस, लोकमत, पुणे)

जनमन

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सवलती स्तुत्य

दिल्ली सरकारने ईव्ही कारसाठी अनेक सवलती १ जुलैपासून जाहीर केल्या आहेत. तीस लाख रुपयांपर्यंत इलेक्ट्रिक कार्सना कर व नोंदणी शुल्कात शंभर टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी केल्यास पहिल्या वर्षी तीस हजार, दुसऱ्या वर्षी तीस हजार, तर तिसऱ्या वर्षी दहा हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास पहिल्या वर्षी पन्नास हजार तर एन-१ या श्रेणीतील वाहनावर खरेदीत तब्बल एक लाखपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

जुने चारचाकी वाहन स्क्रॅप करून इलेक्ट्रिक वाहन घेतल्यास वाहनमालकांना एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांचीच नोंद होईल. तर १ जुलै २०२८ पासून पेट्रोल व डिझेलवरील नवीन वाहनांना परवानगी दिली जाणार नाही. दिल्ली सरकार यासाठी येत्या चार वर्षांत १५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. राजधानी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

दिल्ली शहरात प्रदूषण महाभयंकर असल्याने ही सवलत जाहीर करणे आवश्यक होते. आता दिल्लीत नजीकच्या काळात ईव्ही कार मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जातील व त्याचा फायदा पर्यावरणाला होईल. प्रदूषण कमी करणे ही काळाची गरज आहे. दिल्ली सरकारने टाकलेले पाऊल स्तुत्य आहे. महाराष्ट्रातही मुंबई, पुणे, नाशिक, इत्यादी अनेक शहरांमध्ये मोठे प्रदूषण आहे. या ठिकाणांचे तसेच इतर राज्यांतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी अशा प्रकारच्या विविध उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.



- शांताराम वाघ, पुणे

तिरकस आणि चौकस



ते अभ्यास-विषयास सगळं ठीक आहे मंडम. पण उद्या पेपर फुटले तर जबाबदार कोण ?

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभांमध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : Janman@lokmat.com

गजानन घोंगडे

विशेष • कुछ करने के लिए अभी देर नहीं हुई, लेकिन छोटे-मोटे बदलावों का समय निकल चुका है...

हमें बच्चों को डिजिटल-दुनिया से बचाना होगा

नई पीढ़ी

इमानुएल मैक्रों
फ्रांस के राष्ट्रपति



सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग से लेकर जनरेटिव एआई तक- डिजिटल दुनिया हमारे जीवन और स्वास्थ्य को दृष्टा तय करने वाला मजबूत फैक्टर बन चुकी है। इसमें भी यह विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए और ज्यादा सच है। दुनिया भर में, बचपन को डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और वहीं अब यह तय कर रही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, खेलते हैं और आपस में जुड़ते हैं।

हमारा काम किसी भी टेक्नोलॉजी को निंदा करना नहीं है। लेकिन हमें इस सच्चाई का सामना करना होगा कि डिजिटल-वातावरण दूरीयता लाने का वादा तो करता ही है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करता है। हमारी जिम्मेदारी लोगों को अधिकतम करना और जोखिमों को पूरी तरह से रोकना है।

कुछ करने के लिए तो अभी देर नहीं हुई है, लेकिन केवल छोटे-मोटे बदलाव करने का समय अब निकल चुका है। डिजिटल उपकरण लॉगिंग, कम्प्यूटेशन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में अवसरों का विस्तार कर सकते हैं, विशेष रूप से दूरदराज या संकट-ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए। वे कई युवाओं को ऑनलाइन स्पेस में रचनात्मकता, कम्प्यूटिंग और जुड़ाव को भावना भी देते हैं। यह विशेष रूप से उनके लिए मान्य रखता है, जो ऑनलाइन दुनिया में उपेक्षा का सामना करते हैं। लेकिन ये लाभ गैरिटीड नहीं हैं, वे इस पर निर्भर करते हैं कि एक्सेस किसे है, तकनीकों को कैसे डिजाइन किया गया है, और वे किसके हितों का पोषण करती हैं।

सकॉरों तेजी से यह स्वीकार कर रही है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा अब एक पब्लिक-हेल्थ अनिवार्यता बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला ऐसा नियम लागू किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट खोलने से रोकते हैं। फ्रांस भी 15 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून ला रहा है। इंडोनेशिया ने 16 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्पेन ने ऐसा करने की योजना की घोषणा की है। आयर्लैंड 16 से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित एज-रिस्ट्रिक्शंस और एज-यूथरिंस सिस्टम को विकसित करने के लिए यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ काम कर रहा है।

यूके ने भी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है, साथ ही लाइव-स्ट्रीमिंग और अजनबियों से सम्पर्क पर प्रतिबंध जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी किए हैं। कनाडा ने 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पेश किया है, साथ ही प्लेटफॉर्मों से सेप्टी-बाय-डिजाइन सुरक्षाओं और जवाबदेही की भी मांग की है।

ये तमाम उपाय इस बात पर बढ़ती वैश्विक सहमति को दर्शाते हैं कि डिजिटल वातावरण को प्रभावी गर्नेस, एज-प्रोप्राइट डिजाइन और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज और कल की टेक्नोलॉजी के प्रभाव को स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए जरूरी रिसर्च को बढ़ावा देकर, देशों को तकनीकी सलाह प्रदान करके और सुरक्षित, समान डिजिटल-स्वास्थ्य वातावरण को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहा है।

हमें समाधानों की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल-दुनिया तटस्थ नहीं है। उसे किस तरह से डिजाइन किया गया है, कैसे संचालित किया जा रहा है और उससे कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स हमारे जीवन के कई पहलुओं को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, रूढ़िवादी, सेक्सुअलाइज्ड, हिंसक या भेदभावपूर्ण सामग्री के बार-बार एक्सपोजर से बच्चों की स्वयं और अपने



बच्चों के नजरिये को गहराई से प्रभावित किया जा रहा है

डिजिटल-दुनिया तटस्थ नहीं है। उसे किस तरह से डिजाइन किया गया है, कैसे संचालित किया जा रहा है, उससे कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स हमारे जीवन को आकार देते हैं। सेक्सुअलाइज्ड, हिंसक या भेदभावपूर्ण कंटेंट बच्चों के लिए खतरनाक है।

आस-पास की दुनिया की समझ को गढ़ा जा सकता है। एल्गोरिदम सटीक जानकारी के बजाय ध्यान आकर्षित करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। प्रोफाइलिंग और टारगेटेड-मार्केटिंग के लिए पर्सनल डेटा का संग्रह और उपयोग चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सत्यता है कि अत्यधिक डिजिटल-सम्पर्क से विशेष रूप से किशोरों में एंजयटी, अवसाद, खराब नींद, आक्रामकता और यहां तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ती है।

सोशल मीडिया, गेमिंग और एआई का उपयोग अवैलेपन को गहरा सकता है और ऑफलाइन रिश्तों को विस्थापित कर सकता है। ऑनलाइन यौन-शोषण और

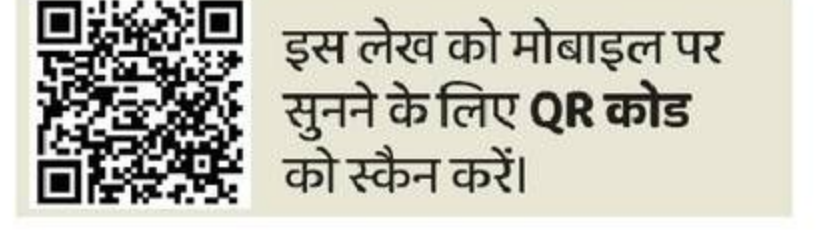
दुर्व्यवहार भी वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं। एआई-जनित एक्सप्लिकिट कंटेंट और झीपेक वाली सेक्सुअल या बुलीइंग वाली सामग्री में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई प्लेटफॉर्मों तो ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें हानिकारक सामग्री के सम्पर्क से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुविधाएं नहीं हैं।

बच्चों की केल-बैंडिंग के मामले में जनरेटिव एआई जॉर्जियों और अवसरों, दोनों को बढ़ाने वाला है। जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए तो विशेष रूप से बनाए गए एआई उपकरण शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों, एमपीथी या सेल्फ-कंट्रोल को लेकर उनका दीर्घकालिक प्रभाव फिलहाल तो अस्पष्ट ही है। वैसे में अगर उन्हें लेकर हम एक सतर्कतापूर्ण रवैया अख्तियार करें तो इसे इनोवेशन का विरोधी होना नहीं माना जाना चाहिए।

सबसे बढ़कर, हमें आज के युवाओं की सुननी चाहिए। टेक्नोलॉजी के एक्टिव-यूजर्स के रूप में वे डिजिटल-वातावरण को जिम्मेदारी से विकसित करने में मदद कर सकते हैं। जरूरी सुरक्षा-दिशानिर्देशों को आकार देने के लिए युवाओं को अपने स्वयं के जीवंत अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। पेंटस, केयर-गिवर्स, स्कूल और कम्प्युटिंग का भी इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए।

हमारे बच्चे और युवा कोई बाजार की कमीडिटी नहीं हैं, या वो ऐसे प्रणी नहीं हैं जिन पर कोई परीक्षण किए जाएं। हमें मिलकर ही ऐसे डिजिटल-वातावरण का निर्माण करना होगा, जो उनके स्वास्थ्य-विकास की रक्षा करे और उसमें उनकी मदद करे। हमारे आज के निर्णय आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे।

(‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’ से। इस लेख के सहलेखक डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसुस हैं।)



इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

प्रेरणा

बुद्धिमान वह है जो सीखता है। ताकतवर वह है जो इच्छाओं को काबू में रखता है। - बेंजामिन फ्रेंकलिन

संपादकीय

बुजुर्गों की आबादी के अनुपात में सामाजिक सुरक्षा जरूरी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवजात और शिशुओं के लिए नया समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। नारा होगा पहले तीन साल, सम्पूर्ण देखभाल। पीएम ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत का नारा देकर हर साल 3% की दर से कमी लाने को कहा था। लेकिन एनएफएस-5 की रिपोर्ट में स्थिति विपरीत पाई गई। बहरहाल, जन दर में कमी के कारण 15 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत पिछले 10-15 वर्षों में लगातार घटा है, जबकि बुजुर्गों का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। जहां सरकार को नवजात शिशुओं में देश का भविष्य देखना चाहिए, वहीं यह न भूलें कि ये वृद्ध निजी तौर पर आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं और नव-औद्योगिकरण ने मां-बाप और उनकी आली पीढ़ी के बीच फासला बढ़ा दिया है। युवा विदेश या बड़े शहरों में रोजगार के लिए जाने को मजबूर हैं। ऐसे में वृद्ध मां-बाप को जीवन चलााने के लिए या बीमारी के दौरान इलाज और देखभाल के लिए कोई सहाय नहीं होता। यूएन पापुलेशन प्रॉस्पेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2000 के मुकाबले बुजुर्गों की संख्या चार गुनी बढ़कर 16.8 करोड़ हो चुकी है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लहर हैं कि कोई बुजुर्ग तो छोड़िए, सक्षम व्यक्ति भी उस व्यवस्था से सुचारु सेवाएं नहीं ले सकता। यही कारण है कि स्वास्थ्य और इलाज पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार को नई कल्याणकारी नीतियां लाकर इन बुजुर्गों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com



प्रकृति और मनुष्य के बीच भी भावनात्मक संबंध बढ़ें

पेड़ भी कुछ कहना चाहते हैं। यह प्रकृति के पक्ष में बोली जाने वाली आदर्श पंक्तियां नहीं, इसके पीछे एक सच काम कर रहा है। 20 से 100 किलोहर्ट्ज पर पेड़-पौधे आवाज करते हैं और इसे दूसरे पेड़ और कुछ जानवर सुनते भी हैं। इसके वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं। जैसे शीत पलों में पेड़ कुछ गुनगुनाते हैं। उनके फूल तोड़ने पर वो आहत नहीं होते। अब धीरे-धीरे मनुष्य को चाहिए कि वो पौधों की आवाज सुने और ऐसा हो भी सकेगा। जो मनुष्य अपनी आत्मा पर बहुत अधिक टिकेंगे, आत्मा के निकट होंगे, वो पेड़-पौधों की आवाज सुन सकेंगे। प्रकृति और मनुष्य के बीच जो भावनात्मक संबंध है, वो और बढ़ना चाहिए, वरना मनुष्य से मनुष्य के बीच का भावनात्मक संबंध तो बिगड़ना ही। जघन्य अपराध पहले पुरुषों के खाते में ही जाते थे। अब कुछ बहन-बेटियां भी सीमाएं लांघ रही हैं। अपराध हुआ, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान हुआ कि परिवारों में एक-दूसरे के रिश्ते पर संदेह खड़े हो गए। प्रकृति से हम जितने दूर होंगे, उतने ही हिंसात्मक, आक्रामक और निर्गतिव हो जायेंगे।

• Facebook: P. Vijayshankar Mehta

राष्ट्रों का जादू

हिस्सेदारी

वह जो पुल के नीचे सोया है, उसकी नाँद में शहर का शोर क्यों नहीं आता?

शायद वह थक चुका है- इंसाफ की उन फहलों की तरह जिन पर वक्त की धूल अब पत्थर हो गई है।

उधर, चमकती कोठियों की देहरी पर एक औरत रोज अपना वजूद बुहारती है, और कूड़े के ढेर में बचपन अपना खोया हुआ खिलौना ढूंढता है।

हम सब इस तमामों में शामिल हैं, कोई चुपकी ओढ़कर, कोई चीख बेचकर।

पर क्या कभी सोचा है- जिसकी नाँव में इतना अन्याय दबा हो, वह छत हमें रिस छुपाने की जगह देगी?

या बस एक भारी बोझ बनकर गिर जाएगी? -विनेश चौधरी, उत्तर प्रदेश (मूल कविता के सम्पादित अंश)

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

मोबाइल चलाएंगे तो काम कब करेंगे?

सरकारी और निजी संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा मोबाइल और सोशल मीडिया का अति-उपयोग उनकी उत्पादकता एवं प्राक्क-सेवाओं पर विपरीत असर डालता है। जिन संस्थाओं में संभव हो, वहां काम के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इससे उत्पादकता और प्राक्क-सेवा का स्तर सुधरेगा। -विनय मोघे, पुणे, महाराष्ट्र

पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो

केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सड़क हदसों का शिकार बनने वाले पैदल यात्रियों में से 30% राष्ट्रीय राजमार्गों पर जान गंवाते हैं। इतने चिंताजनक तथ्य को देखते हुए सरकार को पदयात्रियों के लिए सुरक्षित वॉक-वे मुहैया कराना चाहिए। -हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, मध्यप्रदेश

आप अपने पत्र editpage@dbc.org.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

‘डाइविंग बेल’ है पानी की इकलौती मकड़ी

‘डाइविंग बेल’ दुनिया की एकमात्र मकड़ी है, जो पूरा जीवन पानी में बिताती है। इसकी खासियत है कि यह पानी के भीतर सपन रेशम का घंटीनुमा जाल बनाती है। फिर बार-बार सतह से लाए गए हवा के बुलबुलों को इसमें भरती रहती है। यही गुणवत्त उसका अणुसंश्लेषण टक बना रहता है। 24 घंटों तक अपने घंटीनुमा जाल में रह सकती है। डाइविंग बेल।

सुखियों से आगे • राम-धन की चोरी से देश आहत

सुखों के साथ अयोध्या ने कई दारुण दुःख भी देखे हैं

राम मंदिर

नवनीत गुर्जर
navneet@dbc.org.in



देशभर में हल्ला है। राम मंदिर का और मंदिर की दानपेंटी से चोरी का। कोई कह रहा है- बड़े-बड़ों को छोड़ दिया है। छोटे पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कहना है जो भी दोषी होगा, सजा से बच नहीं पाएगा। राम-धन की चोरी कम से चल रही थी और कितनी हो चुकी, कोई नहीं जानता। किसी के घर से सोना-चांदी बरामद हो रहा है। किसी के घर से मंदिर की संकूह ही जब्त हो रही है। जांच में आखिर क्या निकलेगा, पता नहीं। हल्लाकि इस मामले में कौन, किसको बचा रहा है, कौन किसे फंसा रहा है, इसका प्रामाणिक निष्कर्ष तो सामने नहीं आ सकता है लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एसआईटी पर किसी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव न आने पाए। हो सके तो जांच अदालत की निगरानी में कराई जाए। दान राशि का निष्पक्ष और स्वतंत्र ऑडिट नहीं होगा, तब तक चोरी की रकम का अनुमान लगाना दुष्कर होगा।

इस घटना ने अयोध्या के महत्व को भी प्रभावित किया है। अयोध्या का पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसमें अयोध्या को देवताओं की नगरी बताया गया है : ‘अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या’। देवताओं की नगरी कदाचित्त इसलिए कि ब्रह्मा के मानसपुत्र मनु ने इसकी स्थापना की थी। माना जाता है इसका निर्माण भगवान विष्णु की सलाह पर स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा की देखरेख में हुआ था। स्कंदपुराण के अनुसार, अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि अयोध्या को पहली बार विस्वस्त (यानी सूर्य) के पुत्र वैश्वस्त मनु ने बसाया था।

अयोध्या के लिए इस तरह की घटनाएं नहीं हैं। देवताओं की इस नगरी ने बल, प्रताप और बलिदान देते तो दुःखों के पहाड़ भी झोले। ऋषितुल्य राजा मांधाता का साम्राज्य देखा तो राजा हरिश्चंद्र की सत्यव्रिता और वचन की खातिर रजपाट त्याग देने, यहां तक कि भर-मिटने तक का बलिदान भी देखा। भगते रथ के टूटे पहिए में अपनी अंगुली लगा देने वाला कैकेयी का त्याग देखा तो राम को वनवास भेजने वाले उन्हें कैकेयी के हठ की ही सखी रही। अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की

गई तो इसकी पीड़ा का भी पारवार नहीं रहा। पुत्र वियोग में दारुण का प्राण त्यागना हो या भरत का राजपाट छोड़कर पादुका पूजन हो, सबकुछ आज भी अयोध्या की आंखों में झिलमिलाता रहता है। लक्ष्मण की चौहद साल की सेवा हो या उर्मिला का विवाह, ये सब सिहरन पैदा करने वाले पल रहे। नेता से कल्याण तक की अगिनी कहानियां इस नगरी की छतों में धंसी हुई हैं। इन्हें एक-एक करके निकालना अपने ही दुःखों की सुइयों पोरों से निकालने की तरह है।

जिस राम मंदिर में आज लोग रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं, उस जन्मभूमि के लिए कोई साढ़े चार सौ वर्षों तक संघर्ष चला। कभी संतो और धर्मगुरुओं ने इस आंदोलन की कमान संभाली तो कभी राजनीतिक दल और उनके नेता भी इसमें शरीक हुए। केवल इस आंदोलन के कारण कई सरकारें तारा के पत्तों की तरह गिरी थी और एक अजीब आंधी की तरह आई और बनी

अयोध्या के इस राम मंदिर के लिए सैकड़ों, हजारों लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया है और अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है। उनकी आत्मा को इस तरह की चोरी की घटनाओं से कितना आघात पहुंचा होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।

भी। आंदोलन को पहली बार उभरा तब मिली, जब बाबरी के ताले खोल दिए गए। दरअसल, शाहजहांन प्रकरण पर उग्र हुई मुस्लिम लॉबी के दबाव में जब केंद्र सरकार ने जलदबाजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया तो मंदिर आंदोलन की उभरा चरम की तरफ बढ़ने लगी। सरकार ने शाहजहांन प्रकरण से माफूस हिंदुओं को खुशा करने के लिए बाबरी के बंद पड़े ताले 1 फरवरी 1986 को खोल दिए। किसे पता था बाबरी के बंद तालों के भीतर आंदोलन की आग दबी पड़ी थी। अशोक सिंघल के शिलासूजन अभियान ने आंदोलन को घर-घर तक पहुंचा दिया।

आज अशोक सिंघल जीवित होते तो उन्हें कैसा लगात। जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही राम मंदिर के लिए संघर्ष करते गुजार दिया और आखिर में यह कहते हुए प्राण त्याग दिए कि राम मंदिर बनते हुए देखा ही मेरी अंतिम इच्छा है!

डिफ्रंट एंगल • हम घर का कचरा तो बुहार देते हैं, लेकिन बड़े घर यानी पर्यावरण को दूषित क्यों करते हैं?

ये पृथ्वी हमारा बड़ा घर है, अपने घर की तरह इसे भी साफ-सुथरा रखें

क्वांटमेट

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी
आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर
chetan@iitb.ac.in



हमारे दो घर होते हैं- एक छोटा और एक बड़ा। एक घर तो वह चारदीवारी है, जिसे हम अपना घर मानते हैं। उसमें हमारा सोफा होता है, डाइनिंग टेबल होता है, बिस्तर होता है। हम इस छोटे घर का विशेष ध्यान रखते हैं। उसे साफ रखते हैं और उसे सहेजते हैं, क्योंकि वह हमें सुरक्षा देता है। वह हमें धूल, गर्मी, ठंड, हवा और बारिश से बचाता है। इसी तरह हमारा एक बड़ा घर भी है, हमारी धरती का वातावरण। यह भी हमें सुरक्षा देता है। यदि यह बड़ा घर न हो, तो सूर्य की किरणें इतनी तीव्र हों कि हम उन्हें सहन न कर सकें। या धरती का तापमान इतना कम हो जाए कि यहीं जीवन संभव न रहे। परंतु इसके बावजूद- क्या कारण है कि हम अपने इस

बड़े घर का ध्यान नहीं रखते? यदि पर्यावरण में बहुत अधिक गर्मी हो जाए, बहुत अधिक ठंड पड़ जाए, या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो उसका असर हम पर पड़ता है। कुल मिलाकर पर्यावरण में जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन हम जो कुछ करते हैं, उसका प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है। वास्तव में, आधुनिक जीवन में मनुष्य का शायद ही कोई ऐसा कार्य है, जिसका पर्यावरण पर प्रभाव न पड़ता हो। और दुर्भाग्य से, हमारे अधिकांश कार्य पर्यावरण को सकारात्मक नहीं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह पर्यावरण, हमारा यह बड़ा घर, हमें जीवन देता है। यही हमें हवा देता है, पानी देता है, भोजन देता है और जीवन जीने योग्य परिस्थितियां प्रदान करता है। लेकिन बदले में हम इसे क्या देते हैं? हम इसे गंदा करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण डालते हैं। जब-जब हम खाना फकाते हैं, ट्रेवल करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तब-तब हम कार्बन डाइऑक्साइड रूपी अदृश्य कचरा पर्यावरण में छोड़ते

हैं, जो धरती के तापमान को बढ़ाने का काम करता है। हम सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण फैक्टरियां से होता है। नहीं, वह हमारे रोजमर्रा के जीवन में फैक्टरियों में बनाए सामान के अनियंत्रित उपभोग के कारण होता है। हम सब रोज ही, या सच कहें तो हर मिनट ही अदृश्य कचरा फैक्टर वातावरण रूपी हमारे बड़े घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बार मैंने अपने एक व्याख्यान में श्रोताओं से कहा, मैं आप सभी को थोड़ा-थोड़ा कचरा देता हूँ। क्या आप इसे अपने घर ले जाकर अपने ही घर में फेंक देंगे? सबसे तुरंत मना कर दिया। किसी ने कहा, पानी डालेंगे। किसी ने कहा, मां नाराज हो जाएगी। तब मैंने उनसे पूछा, जब हम अपने छोटे-से घर में भी कचरा नहीं फेंक सकते, तो अपने उस बड़े घर में कचरा कैसे फेंक देंगे? जो हमें जीवन देता है।

आज देश-दुनिया में बेमौसम बारिश हो रही है, ठंडे यूरोप में जानलेवा हीटवेव चल रही है, जंगलों में आग लग रही है। मौसम का जो यह असंतुलन हम देख रहे हैं, जो धरती के तापमान को बढ़ाने का काम करता है। हम सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण फैक्टरियों से होता है। नहीं, वह हमारे रोजमर्रा के जीवन में फैक्टरियों में बनाए सामान के अनियंत्रित उपभोग के कारण होता है। हम सब रोज ही, या सच कहें तो हर मिनट ही अदृश्य कचरा फैक्टर वातावरण रूपी हमारे बड़े घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बार मैंने अपने एक व्याख्यान में श्रोताओं से कहा, मैं आप सभी को थोड़ा-थोड़ा कचरा देता हूँ। क्या आप इसे अपने घर ले जाकर अपने ही घर में फेंक देंगे? सबसे तुरंत मना कर दिया। किसी ने कहा, पानी डालेंगे। किसी ने कहा, मां नाराज हो जाएगी। तब मैंने उनसे पूछा, जब हम अपने छोटे-से घर में भी कचरा नहीं फेंक सकते, तो अपने उस बड़े घर में कचरा कैसे फेंक देंगे? जो हमें जीवन देता है।

हैं, वह प्रकृति की प्रतिक्रिया है। यह प्रकृति का हमें यह बतावना का तरीका है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि यदि आप प्रकृति होते, तो शायद आप भी सभी को ऐसी ही सजा देते। आखिर हम उसके घर में कचरा जो फैला रहे हैं, उसके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य बना रहे। जो कचरा हम धरती पर फेंक रहे हैं, उसकी सजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। यह कट्ट सत्य हमें होश में लाने के लिए है। हो सकता है इसी से हमारा पर्यावरण सुधार का सही काम चल्त हो जाए। और हम सीमित धरती-जिम्मे संसाधन भी सीमित हैं- पर अपनी जरूरतों को भी सीमित करने की शुरुआत कर दें।

जलवायु सुधार टेक्नोलॉजी या नियम-कानून से शुरू नहीं होता। यह जागरूकता से शुरू होता है। संयम से शुरू होता है। यह हममें से हर एक द्वारा अपने बड़े घर के साथ उसी सम्मान से पेश आने से शुरू होता है, जैसा हम अपने बेडरूम के साथ करते हैं। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

बिज़नेस ट्रीफ

फास्टैग: सालाना पास कुल टोल ट्रेफिक का अब 19%

नई दिल्ली | फास्टैग का सालाना पास (₹3,075 में 200 ट्रेफि) जून में कुल टोल ट्रेफिक के 19% तक पहुंच गया। दिसंबर, 2025 में यह 13% था। बीते जून में 44.4 करोड़ में से सालाना 8.4 करोड़ ट्रेफि पास से हुए। इससे एनएचआई को ₹700 करोड़ की मासिक आय हुई। नियमित हाईवे यात्रियों को भी फायदा हो रहा है।

मैनुफैचरिंग 3 माह में सबसे धीमी, निर्यात कम

नई दिल्ली | जून में देश का मैनुफैचरिंग पीएमआई मई के 55 से घटकर 54.2 पर आ गया। एचएसबीसी सर्वे के मुताबिक, कम निर्यात मांग इसकी सबसे बड़ी वजह रही। इससे आउटपुट, नए ऑर्डर और हायरिंग धीमी पड़ गई। इस बीच अंतरराष्ट्रीय मांग सबसे कमजोर रही।

शांफिंग मॉल्स के दम पर रिटेल लीजिंग 18% बढ़ी

मुंबई | अप्रैल-जून में रिटेल लीजिंग 17.6% बढ़कर 24 लाख वर्ग फुट हो गई। कुशमैन एंड वेकफ़ील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें अकेले शांफिंग मॉल्स की हिस्सेदारी 51.3% रही। 64% रिटेल लीजिंग दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद में हुई। ग्रेड-ए मॉल्स में वैकेंसी 5% रह गई। 82% लीजिंग में घरेलू ब्रांड्स सक्रिय रहे।

माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर 2.5% छंटनी करेगी

न्यूयॉर्क | माइक्रोसॉफ्ट अगले हफ्ते ह्यूमन कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रही है। कंपनी कुल 2.28 लाख कर्मचारियों में से 2.5% को बाहर का रास्ता दिखाएगी। सबसे ज्यादा सेल्स, कंसल्टिंग और एक्सबांसिव डिवीजन के कर्मचारी प्रभावित होंगे। यह 2025 की बड़ी छंटनी के बाद नई कटौती है।

सेबी ने 221 संस्थाओं पर 7 साल की पाबंदी लगाई

मुंबई | बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को 2017-20 के बीच 5 श्रेणियों में बड़े पैमाने पर 'पंप-एंड-ड्रॉप' करने के लिए 221 संस्थाओं (हनीफ शेख समेत) पर 7 साल तक प्रतिबंध लगा दिया। शेख पर ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया। आरोप है कि शेख ने 143.79 करोड़ की अवैध कमाई की है।

आंत्रप्रेन्योरशिप • अब 20 साल के भारतीय फाउंडर्स बना रहे सैकड़ों करोड़ की कंपनियों, हर 4 में से 1 डीपटेक या हार्डटेक सेक्टर में झंड़े गाड़ रहे देश में 30 से कम उम्र के 102 उद्यमियों ने खड़े किए 2.9 लाख करोड़ के स्टार्टअप

भारत न्यूज | मुंबई
भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बदल रहा है। युवा उद्यमी अब सिर्फ एप और इंटरनेट बिजनेस तक सीमित नहीं रहे। ये डीपटेक, हार्डवेयर, एआई और ईवी जैसे हाई-टेक सेक्टर में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। 'एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया अंडर-30 लिस्ट 2026' में 102 युवा उद्यमी शामिल हुए, पिछले साल के 80 के मुकाबले 28% ज्यादा। इनकी कंपनियों की कुल वैल्यू ₹2.9 लाख करोड़ हो गई है। फाउंडर्स की औसत उम्र 28 साल है, जबकि सबसे युवा उद्यमी सिर्फ 20 साल के हैं। लिस्ट में हर चार में से एक उद्यमी डीपटेक या हार्डटेक सेक्टर से जुड़ा है। एआई, स्पेसटेक, साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे सेक्टरों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है।

टॉप-10 ने जुटाए ₹33,000 करोड़, दी 75,000 नौकरियां

| कंपनी | कुल फंडिंग |
|-------------|------------|
| फिक्सल | ₹914 करोड़ |
| क्लैरिटी | ₹857 करोड़ |
| विस्पर एआई | ₹771 करोड़ |
| डिजांतरा | ₹638 करोड़ |
| रिविवा | ₹514 करोड़ |
| ट्रायोमिक्स | ₹485 करोड़ |

सबसे ज्यादा फंडिंग इन्हें

जेटो **₹21,897**
भारतपे **₹6,188**
आंकड़े करोड़ में

टॉप-10 संस्थापकों में से 2 सिर्फ 20 के

| | |
|-----------------------|-------------------|
| ओंकार सिंह बत्रा (20) | धव्य शाह (20) |
| अपीलिक | सुरमेमोरी |
| नमन पुष्पा (21) | एयरबाउंड |
| आदित्य पाटील (23) | कैवल्य वोहरा (23) |
| जेटो | |

भारत किरसा
ओंकार सिंह बत्रा

14 की उम्र में सैटेलाइट प्रोजेक्ट, अब ₹400 करोड़ की कंपनी

कोविड के दौरान 14 वर्ष के ओंकार सिंह बत्रा ने ओपन-सोर्स नैनो सैटेलाइट का स्कूल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। ₹23 लाख के इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पता चला कि सैटेलाइट को लगातार जोड़े रखने वाली तकनीक की कीमत 3.8 करोड़ है। समझ आया कि छोटे सैटेलाइट्स की बड़ी चुनौती कनेक्टिविटी है। यही चुनौती दूर करने के लिए उन्होंने 427 करोड़ का स्पेस-टेक स्टार्टअप अपोलिक खड़ा किया।

डीपटेक का दबदबा, हर नई कंपनी ईवी से जुड़ी

हर चार में से एक उद्यमी डीपटेक या हार्डटेक सेक्टर से है। लिस्ट में एआई-मशीन लर्निंग की 6 कंपनियों के 8 फाउंडर्स शामिल हैं। स्पेसटेक, ईवी, एयरोस्पेस-डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी भी उभरते सेक्टर हैं। ऑटोमोबाइल-ऑटो कंपोनेंट्स सेगमेंट एक साल में दोगुना से ज्यादा हो गया, और हर नई कंपनी ईवी से जुड़ी है।

23-29 साल की 6 महिला उद्यमी: लिस्ट में 23-29 साल की 6 महिला उद्यमी हैं। प्रॉन्टो की अंजलि सरदाना, कावा एथलीजर की श्रेया व रिया मिश्र, ऑटोस्केन की देविता घोलप, रिक्लमेटिक्स की देवांशी केजरीवाल और आरएएस लज्जती स्किनकेयर की सुरम्या जैन। इनमें 4 पहली बार शामिल हुई हैं।

40 संस्थापक गैर-मेट्रो शहरों से: बेंगलुरु ने लिस्ट में टॉप पोजिशन वापस पाई (21 उद्यमी, 14 नए), मुंबई अब दूसरे और गुरुग्राम तीसरे नंबर पर है। लिस्ट के 40 फाउंडर्स गैर-मेट्रो शहरों से हैं।

भारत एनालिसिस 10 बड़ी आईटी कंपनियों का मार्केट कैप ₹19 लाख करोड़ घट चुका

जेन एआई आईटी कंपनियों का काम छिन रहा, टॉप-4 शेयर पीक से 57% तक टूटे

भारत न्यूज | मुंबई
घरेलू आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। ये टूट अब सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था में उठापटक का नतीजा नहीं रहा। विश्लेषकों के मुताबिक, यह नई टेक्नोलॉजी जेनरेशन एआई से पैदा हुए ढांचागत खतरे की कहानी बन चुकी है। इसने दशकों पुराने बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के चार सबसे बड़े आईटी शेयर-टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एलटीआईमाइंडट्री ऑल-टाइम हाई से 57% तक टूट चुके हैं। 10 प्रमुख आईटी कंपनियों का मार्केट कैप पीक से 19.3 लाख करोड़ रुपए घट चुका है। इस गिरावट की दो बड़ी वजहें हैं- अमेरिका में सख्त होती मौद्रिक नीति और जेनरेशन एआई से कोडिंग व बैक-ऑफिस काम का ऑटोमेशन। यह आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल को सीधी चुनौती दे रहा है। एक्सपर्ट्स अब सिर्फ कमाई में गिरावट नहीं, बल्कि सेक्टर के स्थायी डी-रेंटिंग की आशंका जता रहे हैं। यानी हालात नहीं सुधरे तो आईटी शेयर और गिर सकते हैं।

बड़ी आईटी कंपनियां अभी आधे से भी कम वैल्युएशन पर

| शेयर | पीक से टूटा | मौजूदा भाव | ऑल-टाइम हाई |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| टीसीएस | 57% | ₹1,982 | ₹4,592 |
| विप्रो | 54% | ₹170 | ₹370 |
| एलटीआईमाइंडट्री | 53% | ₹3,546 | ₹7,589 |
| इंफोसिस | 51% | ₹985 | ₹2,006 |

स्रोत: बीएसई

टीसीएस: सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी का मार्केट कैप ₹16,47,587 करोड़ के पीक से ₹7,17,177 करोड़ रह गया है, यानी ₹9.3 लाख करोड़ घट गया।

इंफोसिस: इस दिग्गज आईटी कंपनी का मार्केट कैप ₹8,30,325 करोड़ के मुकाबले अब आधे से भी कम सिर्फ ₹3,99,854 करोड़ में गिरा।

रिस्क बढ़ा: अब पूंजी क्लाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट होगी

डीबीएस बैंक: एआई से जुड़ा ढांचागत खतरा बढ़ रहा

• एआई के बढ़ते इस्तेमाल का सबसे गहरा असर भारत के आईटी सोर्सिंग सर्विसेज सेक्टर पर दिख रहा है, जो निर्यात, रोजगार और रिटर्न का मजबूत आधार रहा है।

• जेनरेशन एआई तेजी से कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट और बैक-ऑफिस प्रक्रियाओं को ऑटोमेट कर रहा है। इससे आईटी सर्विसेज कंपनियों का काम छिन रहा है।

• आने वाले समय में पूंजी क्लाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी की ओर शिफ्ट होगी। दूसरी तरफ पारंपरिक आउटसोर्सिंग मॉडल दबाव में रहेगा।

आईसीआईसीआई प्रू एएमसी: IT सेक्टर वापसी कर सकता है

• डिजिटल कंटेंट बढ़ने के बावजूद पारंपरिक न्यूज पेपर कंपनियों मुनाफे में रही है। ये दिखाता है कि हर बिजनेस हालात के हिसाब से खुद को बदलता है।

• आईटी सेक्टर भी न्यूज पेपर इंडस्ट्री की तरह वापसी कर सकता है। इसमें मौजूदा गिरावट निवेशकों को धारा के विपरीत छोटे दांव लगाने का मौका दे रही है।

कोटक इंस्टी. इक्विटीज: इन्फोसिस की स्थिति बेहतर

• एक्सचेंजर के कमजोर नतीजे, वित्त वर्ष 2026-27 में आय वृद्धि घटकर 3-4% रह जाने की आशंका और गिरती बुकिंग ने आईटी सेक्टर की मुश्किलें बढ़ाई हैं।

• पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते कंपनियों ने खर्च में कटौती की है। लेकिन इंफोसिस अपने टियर-1 क्लाइंट्स के चलते बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है।

सेंसेक्स 444 अंक चढ़ा, पर आईटी इंडेक्स फिर 2 फीसदी टूटा

सेंसेक्स बुधवार को 444 अंक चढ़कर 76,923 पर और निफ्टी 140 अंको की तेजी के साथ 24,006 पर बंद हुआ। एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई। निफ्टी में इंटर्नल, अदाणी एंटरप्राइजेज और नेस्ले इंडिया टॉप गेनर रहे। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स क्रमशः 0.34% और 0.36% चढ़े। आईटी इंडेक्स करीब 2% टूट गया। हालांकि रियल्टी, एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए।

चुनौती • रिटेल लोन में गैर-हाउसिंग कर्ज 58% से ज्यादा

देश में परिवारों का कर्ज जीडीपी के 45.5% पर पहुंचा, ये रिकॉर्ड

विजनेस संवाददाता | मुंबई
देश में आम परिवारों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इस साल मार्च तक भारत का घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी के 45.5% पर पहुंच गया। परिवारों पर यह कर्ज सितंबर 2023 से ही जीडीपी के 42.9% के 5 साल के औसत से ऊपर बना हुआ है।



रिजर्व बैंक की ताजा फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज बढ़ने की मुख्य वजह नॉन-हाउसिंग रिटेल लोन में आई भारी तेजी है। कुल घरेलू कर्ज में इसकी हिस्सेदारी 58.4% तक पहुंच चुकी है। इस श्रेणी के कर्ज होम, कृषि और बिजनेस लोन के मुकाबले काफी तेजी से बढ़े हैं।

इस्तेमाल: आधा कर्ज सिर्फ खपत के लिए

देश में कुल घरेलू कर्ज का करीब आधा हिस्सा अब ही केवल खपत (कंजम्पशन) से जुड़े उद्देश्यों के लिए लिया जा रहा है। यह घरेलू कर्ज का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्पादक (प्रोडक्टिव) कार्यों के लिए लिए गए कर्ज आते हैं। इसके विपरीत, संपत्ति निर्माण (एसेट क्रिएशन) के लिए ली जाने वाली उधारी की रफ्तार तुलनात्मक रूप से काफी धीमी रही है।

हॉम लोन: वसूल न हो पा रहे कर्ज 7 साल में आधे से ज्यादा घट गए

देश में कर्ज जरूर बढ़ा है, लेकिन लोग समय पर अपना होम लोन चुका रहे हैं। इससे बैंकों का फंसा हुआ पैसा (एनपीए) लगातार कम हो रहा है। मार्च 2019 में बैंकों का हाउसिंग लोन का एनपीए (फंसा कर्ज) 1.2% के स्तर पर था। मार्च 2026 तक यह आंकड़ा तेजी से घटकर महज 0.5% पर आ गया, जो बैंकों के लिए राहत की बात है।

हॉम लोन: वसूल न हो पा रहे कर्ज 7 साल में आधे से ज्यादा घट गए

देश में कर्ज जरूर बढ़ा है, लेकिन लोग समय पर अपना होम लोन चुका रहे हैं। इससे बैंकों का फंसा हुआ पैसा (एनपीए) लगातार कम हो रहा है। मार्च 2019 में बैंकों का हाउसिंग लोन का एनपीए (फंसा कर्ज) 1.2% के स्तर पर था। मार्च 2026 तक यह आंकड़ा तेजी से घटकर महज 0.5% पर आ गया, जो बैंकों के लिए राहत की बात है।

उछाल • कारों की रिकॉर्ड बिक्री से ऑटो बाजार चमका जून में बिक्री रिकॉर्ड चार लाख कारें, 25% उछाल

विजनेस संवाददाता | नई दिल्ली
कारों की बिक्री जून में 25% बढ़कर करीब 4 लाख हो गई। पिछले साल जून में यह आंकड़ा 3.22 लाख था। ऑटो इंडस्ट्री में आई इस तेजी के पीछे तीन बड़े कारण रहे- जीएसटी 2.0, बारह लाख रुपए तक की आय पर टैक्स राहत और आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती। से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। भारतिय सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाथों नरजी के मुताबिक, जून में कुल 4 लाख कारें बिकने का अनुमान है। इसमें 2-3 हजार यूनिट की कमी या बढ़ोतरी संभव है।

उछाल: टाटा मोटर्स की बिक्री सबसे ज्यादा 67% बढ़ी

| कंपनी | गाड़ियां बिकीं | ग्रोथ |
|-----------------------|----------------|-------|
| भारतीय सुजुकी | 1,47,187 | 24% |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | 60,393 | 28% |
| टाटा मोटर्स (पीवी) | 62,076 | 67% |
| ह्यूंडई मोटर इंडिया | 39,635 | - |
| टाटाटा क्लिऑस्कर मोटर | 28,441 | 8% |
| जेएसडब्ल्यू एमजी | 7,568 | 30% |
| किया इंडिया | 24,552 | 19% |
| निसाना मोटर इंडिया | 3006 | 129% |

उत्पत्क: जून में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की घरेलू बिक्री में 67% का बड़ा उछाल आया। कंपनी ने कुल 62,076 गाड़ियां बेचीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू बिक्री भी 28% बढ़कर 60,393 यूनिट पर पहुंच गई।

स्मार्ट इंफ्रा • सबसे बड़ा 3-टावर केबल ब्रिज लगभग तैयार



वीजिंग | पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के निंगबो में 1,730 मीटर लंबे योंगजियांग ग्रेड ब्रिज का निर्माण पूरा होने के करीब है। आखिरी स्टील-कंक्रीट गर्डर जोड़ा जा चुका है। यह तीन-टावर वाला केबल-स्ट्रे पुल अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसके 540 और 570 मीटर लंबे दो मुख्य स्पेस इसे इंजीनियरिंग की नई मिसाल बनाते हैं।

न्यू एसेट • मानसून में देरी से मौसम पर दांव, पहले ही माह 20,000 लॉट की ट्रेडिंग 'वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट' रोजाना 20 करोड़ का

भारत न्यूज | मुंबई
एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820 करोड़ तक पहुंचा दे। अब इसमें आम निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। नेशनल कमांडिटी एंड डेरिवेटिव्स पर से के आखिर में लॉन्च 'रेनमूड' कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही माहने करीब 20,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। जून में शहर में सामान्य से कम बारिश रहने से इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल बारिश 820